[श्री हरीशंकर महाले]

चाहिए । इसके साथ साथ राष्ट्र का हित भी देखना चाहिए ।

(iv) REPORTED RETRENCHMENT OF CASUAL WORKERS IN SOUTH EASTERN RAILWAY.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): I would like to raise a matter of great importance under rule 377.

On February 14, 1978, 111 casual workers of unskilled, semi-skilled and skilled categories, who were working under the District Engineer (construction) Kharagpur, South-Eastern Railway have been arbitrarily retrenched. These employees were recruited between may, 1968 and April 1973 and therefore, have been working for nearly ten years and the shortest period has been five years and they have been in continuous service till their retrenchment. It is strange that on the one hand senior employees are being retrenched while on the other, fresh recruitments of about 99 casual workers were made between October 1976 and May 3, 1977 by the same District Engineer. And moreover in 1978 itself, fifty more casual workers of similar categories were recruited by him. There are various schemes of new works which are to be undertaken by the District Engineer (Construction) Kharagpur requiring a large number of employees of similar categories to that of those retrenched personnel. It is also contrary to law to retrench senior employees and continue in employment the juniors. I would request the Government to immediately look into the matter and see that 111 casual retrenched personnel who have acquired considerable experience in their work are immediately taken back in employment so that their experiences and services can be utilised properly. There are sufficient opportunities for fresh employment which can be given to the persons who have been recruited subsequent to the retrenched personnel and they can be continued in service.

The government has taken a vindictive attitude because some of them have gone to court under jurisdiction of article 226. They have not even received their wages for the period they worked, from 16th January to 14th February. Their salary has been withheld although the court granted them liberty to receive the mony. This is being deliberately withheld just because they have gone to court. I request the Ministry of Railways to act promptly in the matter and take back the retrenched employees. People who have been working for more than 10 years have been retrenched because they are casual employees and in the menatime new people are taken in the same division. More experienced people are being put out of job. There are numerous vacancies for taking in new people. Apart from the question of law, the question of propriety and morality is there. This is a very important matter because 111 persons for no fault of theirs have been dismissed. I request the government and the Railway Minister to look into it. I have also written to him. I hope the Minister of Parliamentary Affairs will kindly bring it to his notice so that some immesdiate steps may be taken.

14.25 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now resume further consideration of the following motion moved by Shri Gauri Shankar Rai and seconded by Dr. Sushila Nayar on the 24th February, 1978, namely:—

"That an Address be presented to the President in the following terms:—

'That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Presi-

dent for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 20th February, 1978'

along with the amendments moved:

Shri Nathuram Mirdha.

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उस पर चर्चा चल रही है। जनता सरकार को बने हुए करीब एक साल होने जा रहा है। पिछले एक साल में इसने क्या क्या किया है और इस साल में यह क्या करना चाहती है इसका करीब करीब सारा ब्यौरा सदन के सामने आ चुका है। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया है, रेलवे बजट पेश हो चुका है, जनरल बजट भी कल पेश हो गया है और इस सरकार के क्या इरादे हैं क्या यह करना चाहती है वह सब चीज़ लोगों के सामने आ गई है। मैं सारे मामलों पर एक साथ राय नहीं दे सकता हूं। कुछ मुद्दों पर ही अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पैरा नम्बर 5 में यह अपेक्षा की है कि देश में कुशल और स्वच्छ प्रशासन की आवश्यकता है। सच्चाई यह है कि इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है और इसके बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। पिछले एक साल में जिस प्रकार से केन्द्र और राज्यों में जहां पर जनता पार्टी की सरकारें हैं कार्य किया है उसको देखते हुए क्या यह कहा जा सकता है कि ईमानदारी की भावना बढ़ी है ? जहां तक मेरी राय है प्रशासन में, प्लांज के एक्सीक्यूशन में, चाहे केन्द्र हो या राज्य सरकारें हों जहां जनता की सरकारें हैं शासन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वही ज्यादा से ज्यादा ढीलापन शासन में नजर आता है। चारों तरफ एक अनिश्चितता का वातावरण नजर आता है। अधिकारीगण फैसले तेज़ी से और हिम्मत से कर सकें ऐसा वातावरण कहीं नजर नहीं आता है। मंत्रियों का आपस में तालमेल नहीं है। उनके आपसी झगड़ों की खबरें रोज अखबारों में आती हैं। छोटी छोटी बातों को ले कर उनमें आपस में मतभेद होते हैं। कौन सी नीति पर आप देश को चलाना चाहते हैं और क्या करना चाहते है उसके कोई आसार पिछले एक साल में मुझे तो नजर आए नहीं।

यह कहें कि लोकपाल बिल आएगा और वह पास हो जाएगा तो सारी राजनीति शुद्ध हो जाएगी, शासन अच्छा चलने लग जाएगा तो मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा आकांक्षा उस कानून से कर रहे हैं उसमें पार्लियामेंट के मेम्बरों को भी जोड़ा जा रहा है ताकि वह भी भ्रष्ट न हों, जब कि उनके हाथ में कुछ करने का अधिकार नहीं है। केन्द्रीय मंत्रियों को और राज्य के मुख्य मंत्री को उस दायरे में लाना चाहते हैं। पर उस दायरे में लाये बिना भी शुद्धता लायी जा सकती है, और जिस तरह की मैं आशा करता था वह आज देखने को नहीं मिलती है। कुशल प्रशासन होना चाहिये, इसमें दो रायें नहीं हैं, पर एक साल में उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, और देश आगे किस तरह बढ़ेगा कुछ समझ में नहीं आता।

राष्ट्रपति जी ने इस देश के अन्दर विकास के बारे में कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ग्रोथ 5 परसेंट हुई। पर उसके साथ साथ उन्होंने चिन्ता जाहिर की हैं कि देश के अन्दर आज भी कुछ ऐसे तत्व हैं, चारों तरफ शरारत और गुंडई का वातावरण बना हुआ हैं, ला ऐंड आर्डर की समस्या आज भी देश के सामने है, और मैं समझता हूं कि उनकी चिन्ता वाजिब है। किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है और गरीबी

[श्री नाथू राम मिर्धा]

को मिटाना है जैसा कि यह कहते हैं कि 10 साल में इस काम को कर देंगे, मैं सोचता था कि जो भी नीतियां इनकी हैं उसमें कहीं भी एक बटे 10 के आस पास एक साल में बढ़े हों । लेकिन कहीं नजर नहीं आता । कहीं भी दिखाई नहीं देता कि तिल मात्र भी पहले की स्थिति से आगे बढ़े हों । सिर्फ यह कहना कि कांग्रेस ने 30 साल में खराब काम किये इससे काम चलने वाला नहीं है । जनता प्रमाण चाहती है । उन्होंने अमरीका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड के प्रधान मंत्री के कोटेशन्स दिये है जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता । लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि देश की ग्रोथ बढ़ाने के लिये शांति का वातावरण सब से जरूरी चीज है, जो आज नहीं नहीं है । मजदूरों के क्षेत्र में देखिये, आपने इकोनामिक सर्वे में कहा है कि पिछले साल में लेबर डेज लोस्ट 11 मिलियन, उसके पहले साल में 6 मिलियन । लेबर स्ट्राइक ज्यादा बढ़ी, लोक आउट्स बढ़े हैं । आज भी चिन्तित हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है । वित्त मंत्री जी ने कल बजट में कन्सेशन भी दिये हैं । लेकिन जब तक ला ऐंड आर्डर में सुधार नहीं होता, मजदूरों के बारे में आपकी नीतियां साफ़ नहीं होंगी तब तक हालात बिगड़ते जायेंगे । विद्यार्थियों में जगह जगह पर अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, 24 विश्वविद्यालय बन्द हैं, आज स्कूलों और कालेजों में पढ़ने का वातावरण नहीं है । जो इमरजेंसी के दौरान अनुशासन का वातावरण बना था वह बिगड़ता जा रहा है । सरकारी कर्मचारियों में आज ढीलापन चालू है, अनिश्चितता की स्थिति है । इसी तरह से जरायम बढ़ रहे हैं । दिल्ली में ही अखबारों में पढ़ने को मिला कि पीछे पीछे पुलिस पार्टी चल रही है और आगे आगे चोर घरों को लुटते जा रहे हैं । इस प्रकार जो विद्यार्थियों में, सरकारी कर्मचारियों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है, नागरिकों में सुरक्षा का वातावरण नहीं है और जिसके बारे में राष्ट्रपति जी ने चिन्ता प्रकट की है, समझ में नहीं आता कि किस तरह से आप उसमें सुधार करने जा रहे हैं ।

जिस प्रकार से आपकी शासन व्यवस्था राज्यों और केन्द्र में चल रही है और जिस तरह के तौर तरीके आपके मंत्रियों द्वारा काम में लाये जा रहे हैं, हम रोज देखते है कि प्रधान मंत्री जी को बीच में खड़े हो कर कहना पड़ता है कि शांति रखी जाय, इस वातावरण को किस प्रकार सुधारेंगे, कोई चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देती है । वातावरण में सुधार की आवश्यकता है, वरना आप ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते । आपने कबूल किया है कि इमरजेंसी की वजह से लोगों में जो कमजोरी आयी थी वह दूर हो गई है और लोगों में उछाल आ रहा है । जिस प्रकार गेंद को जितने ज्यादा जोर से नीचे मारोगे उतने ही जोर से ऊपर उछलेगी । अगर आप इसमें सुधार नहीं करते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता । इसलिये मैं आपका ध्यान राष्ट्रपति जी की चिन्ता की तरफ, जिस चिन्ता में मैं अपनी चिन्ता को भी शरीक करता हूं, दिलाता हूं कि देश के हालात को अगर इन बातों में नहीं सुधारा गया, तो निश्चित तौर पर हमारे आगे की ग्रोथ के कोई मायने नहीं हैं ।

आर्थिक ग्रोथ के बारे में आपने खुशी जाहिर की और कहा कि पिछले साल के मुकाबले में, जहां कि 1.6 ग्रोथ थी, अब हमने 5 परसेंट ग्रोथ कर दी । परन्तु इसके साथ ही आर्थिक समीक्षा में यह भी लिखा है कि 75 और 76 की ग्रोथ, जो कि 8. कुछ है, वह पहले से ज्यादा है । उसका मतलब यह हुआ कि तीन साल की बात आपने कही । राष्ट्रपति जी ने 5 साल की ग्रोथ पर खुशी जाहिर की और कहा कि आगे भी ग्रोथ करने जा रहे हैं । यह भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर पर हमने ज्यादा धन लगाया है, 400, 450 करोड़ रुपया इस साल में एग्रीकल्चर, इरिगेशन

फर्टिलाइजर वगैरह पर खर्च करेंगे और बीज ज्यादा देंगे । लेकिन आर्थिक समीक्षा के लास्ट पैरा में लिखा है कि यह केवल तभी संभव होगा जब कि शासन में कुशलता हो । इन्फ्रा-स्ट्रक्चर इन चीजों को चलाने के लिए सक्षम हो । उसमें आपने यह अपेक्षा की है कि गांव लेबल पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों का आपस में तालमेल होकर नये तरीके से हम इस टेक्नौलाजी को काम में ला सकेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि आप ग्रास-रूट लेबल पर क्या करना चाहते हैं, क्या परिवर्तन आप एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहते है ?

कृषि आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप में तबदीली करें । जिन चीजों की देश को जरूरत है, जब तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की ओवरहाल नहीं करेंगे, न आपकी योजना बन सकती है और न चल सकती है और न ही उसक बेसिक इन्फ्रा-स्ट्रक्चर बन सकता है ।

अब एक साल होने आया, कृषि आयोग की 38 वाल्यूम लिखी हुई हैं । आप रात-दिन ग्रामीणों की वकालत करते हैं, उनको ऊंचा लाने की बात सोचते हैं, तो उन सिफारिशों का क्या हुआ जो कृषि आयोग ने देश की थीं ? पूरे का पूरा ढांचा उसका आपके सामने है । काटेज इंडस्ट्रीज और एग्रो-इंडस्ट्रीज की गांवों में किस प्रकार बढ़ाया जाये, लोगों के इकनामिक स्टैंडर्ड को कैसे सुधारा जाये, खेती की प्रोडक्शन कैसे बढ़ायी जाये, आदि पर उसकी सिफारिशों पर कौन ध्यान दे रहा है ?

आपने डैजर्ट डैवलपमेंट के लिये 6 करोड़ रुपया रखा । उसमें से कितना खर्च हुआ है ? अब कहते हैं कि 20 करोड़ रुपया रख देंगे, तो एग्रीकल्चर सैक्टर में रुपया बढ़ाते जायें, लेकिन इससे ही सारा काम नहीं हो जाता । जब तक बेसक इन्फ्रा-स्ट्रक्चर और आम लोगों के सहयोग को इसमें जोड़ कर हम साथ नहीं चल सकते, एग्रीकल्चर की चीजों की कमी को हम पूरा नहीं कर सकते हैं ।

आपने इस बात पर गर्व जाहिर किया कि इस साल अनाज का उत्पादन 121 मिलियन टन हो जायेगा । पिछले दफे 118 मिलियन टन तक पहुंच चुका है । आप कहेंगे कि 2 हजार मिलियन हैक्टर में सिचाई बढ़ायेंगे, फर्टिलाइजर बढ़ायेंगे । यह सब चीजें तो नार्मल फसलों में चल रही हैं परन्तु उसका उपयोग जो पावर्टी लाइन के नीचे लोग हैं, उनमें कितनी क्षमता बढ़ती है, उनकी इकनामिक ग्रोथ क्या होती है, यह देखना जरूरी है ।

राजस्थान के मुख्य मंत्री की पहुत तारीफ करते है । उन्होंने एक योजना बनाई है कि एक-एक गांव में 5–5 परिवारों को सहायता देंगे, रुपया देंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या बेसिक इन्फ्रा-स्ट्रक्चर है, उन 5, 5 परिवारों को गांवों में संभालने के लिए कि लोन देने के बाद पैसा उसी परपज में लगे जिससे उत्पादन बढ़े, पैसा पे करने की कैपेसिटी बढ़े ? इस तरह से रुपया देने और योजना रख देने से देश का काम चलने वाला नहीं है । देश का काम उससे चल सकता है कि हम इन चीजों का उपयोग कैसे कर सकगें हैं, और उसका उपयोग करने शसान की शक्ति है या नहीं ? लोगों का सहयोग उसके साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं ? यह बात बहुत मैटीरियल है ।

आज एग्रीकल्चर में कितने उतार-चढ़ाव देखने में आ रहे हैं । एक माननीय सदस्य ते कहा कि काटन, तेल की कमी हैं और चीनी इतनी पैदा हो गई है कि किसान भी परेशान है, आपकी भी समझ में नहीं आता कि क्या करें ? रुई ज्यादा पैदा हो जाये, तो आपको

[श्री नाथु राम मिर्धा]

चिन्ता हीं जाती है कि क्या करें । आपकी पार्टी में बैठने वाले लोग इस तरह के मुद्दों से हमेशा चिन्तित रहते हैं । अगर पैदावार बढ़ जाये, तो उस चीज का भाव गिर जाता है, उसकी मार्केटिंग की उचित व्यवस्था नहीं है ।

इस तरह से और भी चीजें हैं, बड़े-बड़े नारे लगाये जाते है । धारिया जी कहते हैं कि 15, 20 एसैंशियल कमोडिटीज की वितरण की व्यवस्था सुधारेंगे, प्राइस एस्टैब्लिश करेंगे, सब चीजें वाजिब तौर से लोगों को मिलेंगी । कहना आसान है, परन्तु करेंगे कैसे ? आपकी रिपोर्ट में है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिये । लेकिन उसकी मार्केटिंग की क्या व्यवस्था हो, किस प्रकार से रुई को डील किया जाये, किस प्रकार आयल-सीड को डील किया जाय किस तरह से और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को मार्केटिंग की समस्या को हल किया जाये, सारी बातें बहुत डिटेल में समझा कर उसकी सिफारिशें लिखी हुई हैं ।

कृषि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में 2,333 सफ़ारिशें की हैं । लेकिन किसने पढ़ा है उस रिपोर्ट को ? संसद्-सदस्यों में उसकी समरी बांटी गई हैं, लेकिन सरकार के कितने लोगों ने उसका अध्ययन किया है ?

सरकार की तरफ से रोज़ ग्रामों को ऊंचा उठाने की बात कही जाती है । सरकार की भावना बड़ी शुद्ध है, लेकिन जब तक उस भावन की मूर्त रूप देने के लिए कोई इन्फ्रा-स्ट्रक्चर न हो, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था न हो और पैसे का ठीक उपयोग करने का इन्तज़ाम न हो, सब तक केवल शुद्ध भावनाओं को व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा । मार्केटिंग के उतार-चढ़ाव एग्रीकल्चर को कभी पनपने नहीं देंगे ।

इस बात पर बहुत जोर दया गया है कि हमारी बहुत अच्छी साउंड इकानामी है, हमारे पास 20 मिलियन टन अनाज है, जो और बढ़ता जायेगा, और हमारे पास 4,000 करोड़ रुपये की फ़ारेन एक्सचेंज है । सरकार इस बात पर बहुत खुश हो रही है । लेकिन इस स्थिति पर पहुंचने के लिए उसने क्या किया है ? उसने जोन्ज को ख़त्म कर दिया हैं और फ्री मूवमेंट की इजाज़त दे दी है । अगर लेकिन अगर अगले साल अकाल पड़ गया, तो ब कैसे चावल या गेहूं इकट्ठा करेगी और कैसे उन्हें बांटेगी ?

मेरा निवेदन यह है कि लोगों को खुश करने के लिए डे-टु-डे नीतियां निर्धारित करने का तरीका त तो देश के लिए और न सरकार के लिए हितकर है । जब तक सरकार लांग-रेंज पालिसीज़ बना कर कोई व्यवस्था नहीं करेगी, तब तक न तो प्रोड्यूसर को ठीक दाम मिलेगा और न ही कनज्यूमर्ज को कोई लाभ होगा । आज प्रोड्यूसर रो रहे है, क्योंकि उन्हें वाजिब दाम नहीं मिलता है । कनज्यूमर के लिए प्राइस की कोई गारंटी नहीं है । आज कोई प्राइस स्टैबिलिटी नहीं है । सरकार की तरफ़ से आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि होलसेल इंडेक्स पहले से हाई है, लेकिन कनज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है । मैं भी यही कहता हूं कि जो गरीब लोग रोज़ खरीद कर खाते हैं, उनकी स्थिति में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ।

आज सारी व्यवस्था व्यापारियों, मिडलमैन, के हाथ में है, जो किसानों को ठीक दाम नहीं देते हैं और कनज्यूमर को भी लूट खिसोट रहे हैं। अगर जनता पार्टी कुछ क्लीयर थिंकिंग करके सही नीति नहीं अपनाती है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला है । प्राडक्शन बढ़ता है, तो किसान मरता है, क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं है । अगर प्रोडक्शन घटता है, और

अनाज के भाव ऊंचे होते हैं, तो सब किसानों को गाली देते हैं। सरकार इस स्थिति से कैसे निपटना चाहती है, इसका कोई क्लीयर इंडीकेशन सरकार के किसी भी डाकुमेंट में देखने को नहीं मिला है। हां, अगर मंत्री महोदय अपने भाषण में कोई स्पष्टीकरण दें, तो मैं समझने के लिए तैयार हूं।

मैं आपकी दो बातों की तारीफ़ करना हूं। आपने इसमें जो नेशनल सटेलाइट प्रोजक्ट को स्वीकार किया है इस की रेकमेंडेशन राष्ट्रीय कृषि आयोग ने की थी और यह बहुत जरूरी प्रोजक्ट है। देश की धरती के नीचे कितना पानी है, कितनी धातु हैं उसका सर्वेक्षण आप इससे कर सकते हैं। खेती में बीमारी कितनी हैं, कितनी एकरेज में कितनी फसल है और क्या फसल की हालत है यह सब सैटेलाइट बता सकता है। इस की मैं तारीफ करता हूं।

इसी तरह आप ने चार सालों में शराबबन्दी करने की घोषणा की है, इस का भी मैं हामी हूं। मैं जानता हूं इससे फ़ायदा होगा। मेरे जिले के अन्दर भी पहले लोग लड़ते थे कि नहीं होनी चाहिए लेकिन पिछले तीन चार सालों से जब से शराबबन्दी हुई है उसका फायदा लोगों ने खुद महसूस किया है, यह मैंने देखा हैं। इसलिए चार सालों में अगर आप शराबबन्दी कर दें तो यह देश के हित में होगा। बहुत से जो पीने वाले हैं वे यह कहते हैं कि इस से बूट-लेगिंग होगी। कहने वाले कहते ही रहेंगे, लेकिन शराब अगर इस देश में बन्द हो जाये तो लोगों का नेशनल चरित्र भी ऊंचा होगा, वाजिब तौर पर बचत होगी, परिवार अच्छी तरह से चलने लगेंगे और आर्थिक उन्नति होगी। आपकी इन दो बातों की जो राष्ट्रपति महोदय के भाषण में कही गई हैं मैं तारीफ़ करता हूं। .. (व्यवधान) ..... आप मुझे दो तीन मिनट का समय और दे दें तो मैं अपनी बात कह लूंगा। .....

SHRI A. BALA PAJANOR (Pondicherry): I want to know whether any relaxation has been made in admission to the Central Hall, because there are a number of people there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not raise the question of the Central Hall here Yesterday itself I had made it clear. As far as the Central Hall is concerned, it is the look-out of the Watch and Ward. You can go and complain to them.

SHRI A. BALA PAJANOR: They say it is under the rules.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not raise the matter.

SHRI A. BALA PAJANOR: You can give a ruling.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not consume the time of the House.

श्री नाथू राम मिर्धा : अभी शाह आफ ईरान आए थे तो उनको आपने राजस्थान कैनाल का दौरा कराया था। राजस्थान कैनाल का दौरा करते वक्त मैंने यह भी सुना कि वह भारत सरकार को राजस्थान कैनाल का सैकेंड फेज पूरा करने के लिए कुछ रुपया देना चाहते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान कैनाल और डैजर्ट डैवलपमेंट के बारे में एक बहुत स्पेशल रिपोर्ट लिखी है और उसमें यह कहा गया है कि पानी ज्यादातर जो जा रहा है बहाव के जरिए से पाकिस्तान बार्डर की तरफ उसको लिफ्ट के जरिए उठाया जाए। उस सारे प्रोजेक्ट को रिवाइज करने की ज़रूरत है। कम से कम जिस लिफ्ट की बात को प्लानिंग कमीशन मानता है, भारत सरकार मानती है और राजस्थान सरकार भी पहले मानती थी, अब पोलिटिकल ग्राउन्ड्स पर उसको रिवर्स करना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। जहां लोग बैठे हैं वहां पानी नहीं लाना और जहां कोई नहीं है वहां पानी

[श्री नाथू राम मिर्धा]

को घर घर ले जाना यह देश के लिए बरबादी का दिन होगा । केवल इशारे मात्र में मैं इतना ही कहना चाहता हूं :

रेलवे बजट में भी मैंने देखा राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं है । बेकारी और बेरोजगारी दस साल में दूर करने के प्रोग्राम को भी मैंने समझने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कहीं पर उस का इसमें ट्रेस भी नहीं मिला कि बेकारी और गरीबी मिटाने के लिए रत्ती भर भी कहीं कुछ किया हो । जो प्रोग्राम बनाया हैं उसमें मुझे कोई तथ्य नजर नहीं आता ।

अन्त में मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश में मुझे बहुत विघटन की प्रवृत्तियां नजर आ रही है । आपने फारेन रिलेशंस के बारे में बहुत देशों की अच्छी अच्छी बातें कही हैं । नान एलाइनमेंट पालिसी पर आप चल रहे हैं । कभी कभी जैनुइन शब्द लगा देते है चाहे वह किसी की समझ में आए या न आए । लेकिन मुझ उसकी कोई चिन्ता नहीं है । आप लोग नये नये आए हैं, आप मिलें उन से बातें करें, अच्छे सम्बन्ध बनाएं, देश के हित में बनाएं, यह सब ठीक है । पर देश में जो खराबी हो रही है, एक तो भाषा के नाम पर हीं रही है । फिर देश के ईस्ट में और तरह के तत्व पनप रहे हैं । इधर पंजाब में कुछ और हालत बनती चली जा रही है । मैंने किताबें पढ़ी हैं जिनमें लिखा है कि यह तो हन्दू राज है, उधर वाला मुसलमान राज है । बीच में सिख राज बनाओ । ऐसे भी भाषण चल रहें है । ऐसी किताबें मैं ने पढ़ी हैं । इसलिए देश में आज विघटन की प्रवृत्ति बढ़ रही है । ..... (व्यवधान) ..... आप इन बातों के ऊपर सोचिए । देश के अन्दर अगर ये सवाल उठ कर खड़े होंगे और बिखराव की तरफ जाएंगे तो ये आपकी तरक्की के लिए परेशानी के कारण बनेंगे । मैं चाहूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है उसके ऊपर आप गहराई से विचार कीजिए ।

श्री नाथू सिंह (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । विरोध पक्ष के जो हमारे मित्र इस प्रस्ताव के विरोध में बोल रहे हैं, लगता है उन्होंने हर चीज़ को स्वीकार करने से मुंह मोड़ लिया है । उन्होंने जो इस की आलोचनाएं की हैं उस से लगता है कि उनको आलोचना करना भी ठीक ढंग से नहीं आता हैं । पहले वह कह रहे थे कि जनता पार्टी नहीं चलेगी, जनता पार्टी टूट जायगी । लेकिन जनता पार्टी ठीक प्रकार से चल रही है, उस की सरकार भी बन गई, लेकिन जो कह रहे थे कि जनता पार्टी टूट जायगी, जो जनता पार्टी पर प्रहार कर रहे थे, उन की अपनी पार्टी टूट गई और आज हम देख रहे है कि एक तरफ़ रेड्डी कांग्रेस हैं और दूसरी तरफ लेडी-कांग्रेस है । हमारी पार्टी के लिये एक वर्ष कोई अधिक समय नहीं हैं, हमारी पार्टी की स्थापना हुए ही अभी एक वर्ष हुआ है, सरकार की स्थापना हुए भी एक वर्ष ही हुआ है । अभी तो हम को चुनावों से भी फुरसत नहीं मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग पहले से ज्यादा मजबूत हुए है ।

दूसरी बात ये लोग कह रहे है कि जनता पार्टी विभिन्न स्वरों में बोलती है । मैं उनको बतलाना चाहता हूं–एक स्वर तो केवल तानाशाही में निकलता है, लोकतन्त्र में तो हमेशा विभिन्न स्वर निकलते हैं । आप ने बांसुरी की आवाज़ सुनी होगी, जनता पार्टी कृष्ण की वांसुरी है, जिस में विभिन्न स्वरों के द्वारा जो स्वर निकलता है, वह मीठा ही सुनाई देता है । इस लिये एक स्वर में बोलना तानाशाही की निशानी हैं । पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी एक स्वर में बोलती थीं, मिनिस्टर लोग उन्हीं की बात को दोहराते थे, मुख्य-

मंत्री लोग उसी बात को दोहराते थे, तथा-कथित युवक-कांग्रेस के नेता लोग उसी बात को दोहराते थे । पूरे हिन्दुस्तान में एक ही स्वर सुनाई देता था—चाहे रेडियों हो या समाचार पत्र हों, सभी के माध्यम केवल इन्दिरा जी का स्वर और दूसरा स्वर संजय गांधी का सुनाई देता था, तीसरा कोई स्वर उस जमाने में सुनाई नहीं देता था ।

कल स्टीफ़न साहब ने कहा कि यह तो आयोगों की पार्टी है । हम झण्डे के लिये खून वहा देंगे । मैं स्टीफ़न सहब से पूछना चाहता हूं—आपातकाल के दिनों में आप की बहादुरी कहां चली गई थी ? किस बिल में घुस गई थी, जो आज बहादुरी दिखा रहे हैं ? हम जानते हैं आप कितने बहादुर हैं, झ ंडे के लिये कितना खून बहायेंगे । आपातकाल के दिनों में जब अत्याचार हुए, जिस जनता ने आप को वोट दिया था, जब उस पर अत्याचार हो रहे थे, तो आप की जुबान क्यों बन्द थी ? आप ने खून बहाना तो दूर रहा, पसीना तक नहीं बहाया । इस लिये हम जानते हैं कि आप कितने बहादुर है और झण्डे के लिये कितनी बहादुरी दिखायेंगे ।

आपने कहा कि यह आयोगों की पार्टी है । किसी भी लोकतान्त्रिक देश में जनतन्त्र को कुचलने वालों के ऊपर आयोग बैठाना तो बहुत छोटी सी बात है । आप इंग्लैंड का उदाहरण लीजिये—वहां ऐसी व्यवस्था है कि जो जनतन्त्र के ऊपर प्रहार करे, उस को नष्ट करें, उस पर आयोग ही नहीं, महा-अभियोग लगना चाहिये । हम ने बहुत ही साधारण कार्यवाही की है, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, आप लोगों पर दया कर रहे हैं, लेकिन उस के बावजूद भी आप कहते हैं कि हम आयोग बैठा रहे रहे है । जब आयोग की रिपोर्ट आयेंगी और उस के बाद आप के ऊपर जो कार्यवाही की जायगी, तब पता नहीं आप क्या करेंगे ।

आप कह रहे है कि जनता पार्टी लोकतन्त्र को खोखला कर रही है । स्टीफ़न साहब ने देव राज अर्स का उदाहरण दिया, उन की सरकार को भंग कर दिया गया था और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था । आपात काल के दिनों में जब हम जेलों में बन्द थे, तमिलनाडु का उदाहरण आप के सामने है । आप ने तमिलनाडु सरकार को क्यों भंग किया था ? क्या इस लिये कि श्री करुणानिधि महादेवी के चरणों में सिर नहीं झुकाते थे । जब आप ने उस समय तामिलनाडु की सरकार को भंग कर दिया, तो अब हम ने यदि देवराज अर्स की सरकार को भंग कर दिया—हस में आप को क्यों आपत्ति हैं ? आप को केन्द्र में 6 साल तक बने रहने का अधिकार किस ने दिया था ? आप तो पांच सालों के लिये चुन कर आये थे । उस के बावजूद भी यदि हम चाहते तो कर्णाटक की सरकार को अपने हाथ में रख सकते थे, लेकिन हम ने तुरन्त वहां पर चुनाव करवा दिये और उसके बाद जनता ने जो फैसला दिया, उस को हम ने सहर्ष स्वीकार किया । तो यह कहना कि हम लोकतंत्र की जड़ें खोखली कर रहे हैं सर्वथा ग़लत है । आप ने उस से पहले क्या किया । विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एक झटके में बदल देते थे और इस तरह से आप ने कई मुख्य मंत्री बदल दिये । श्री मोहन लाल सुखाडिया आप के प्रजातंत्र का एक उदाहरण हैं । वे राजस्थान के मुख्य मंत्री थे । उनको आप ने मुख्य मंत्री पद से हटा दिया । क्या उन्होंने वहां की विधान सभा का विश्वास खो दिया था । ऐसी कोई बात नहीं थी लेकिन उन को मुख्य मंत्री के पद से हटा कर गवर्नर इसलिए बना दिया गया था कि वे राष्ट्रपति जी या इन्दिरा जी के इशारे पर नहीं चलते थे । उनके स्थान पर आप ने श्री बरकतुल्ला खान को वहां पर थोप दिया । विधान सभा के सदस्यों से नहीं पूछा गया और

[श्री नाथू सिंह]

न ही अपनी पार्टी के लोगों से आपने पूछा । ऊपर से उन को वहां पर थोप दिया गया । यह था आप का लोकतंत्र, यह था आप का प्रजातंत्र ? इस तरह के एक नहीं बल्कि कई उदाहरण मैं आप के सामने रख सकता हूं जिन से पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना तानाशाही रवैया अपनाया था। प्रेस का गला आप ने घोट दिया था। हम प्रेस आयोग बना रहे हैं। इसके अलावा हम प्रेस को पूरी स्वतन्त्रता दे रहे हैं। आप की तरह हमने न्यायपालिका को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में नहीं किया। हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों को पूर्ण स्वतन्त्रता दी है और वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से काम कर सकती हैं। लोकतंत्र के जो ये पहिये हैं, धुरी हैं, इनको हमने मजबूत किया है। आप यह देखें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, चाहे उन्होंने जैसा फ़ैसला दिया, हमने नियमों का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया है । क्या यह लोकतंत्र का सही नमूना नहीं है ?

एक चीज़ मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि प्रेस के बारे में जो सरकार कर रही है, वह ठीक ही कर रही हैं लेकिन वेज बोर्ड की जो शर्तें हैं उन को बड़े-बड़े अखबारों के मालिक नहीं मान रहे हैं । हो सकता है कि उन के और कांग्रेस के सम्बन्ध कुछ अच्छे रहे हों, इन्दिरा जी के और उन के सम्बन्ध कुछ अच्छे रहे हों, लेकिन कर्मचारियों की जो वाजिब मांगें है और वेज बोर्ड में जो शर्तें रखी गई हैं उन को वे लोग नहीं मान रहे हैं । सरकार बड़े पत्रों के मालिकों को इस बात के लिए मजबूर करे कि वेज बोर्ड की जो शर्तें हैं, उन को वे मानें और इसके लिए उन पर दवाव डालना चाहिए ।

एक बात यह बहुत कहते हैं कि हरिजनों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं । ऐसा कह कर यह छुआछूत की भावना फैला रहे हैं । बनारस के अन्दर क्या हुआ जब बाबू जगजीवन राम जी वहां पर गये थे ? कौन थे वे लोग ? वे जो इन्दिरा कांग्रेस के समर्थक थे, इन्दिरा समर्थक विद्यार्थी थे जिन्होंने वहां के विश्वविद्यालय पर अपना कब्जा किया हुआ है । वे एन० एस० एफ० आई० के विद्यार्थी हैं जो इन्दिरा जी के समर्थक हैं और वे वहां पर लोगों में छुआछूत की भावना फैला रहे है । वहां पर 19 विद्यार्थियों को 30 जनवरी को गिरफ्तार किया गया जिन में वहां की यूनियन का अध्यक्ष भी था और जो इन्दिरा जी का पक्का समर्थक है । क्या यह जनता पार्टी वालों ने किया है. आर० एस० एस० वालों ने किया या किसी सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है ? यह केवल इन्दिरा जी के समर्थकों ने किया है और आज यह दिखाना चाहते हैं कि हरिजनों पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं । जहां तक हरिजनों पर अत्याचार की बात है, 20 प्रतिशत अत्याचार इन के जमाने में हरिजनों पर हुआ करते थे लेकिन अब वे 5 प्रतिशत पर आ गये है । हमारी सरकार को बने हुए अभी एक ही साल हुआ है और 5 प्रतिशत पर हम इन को ले आए हैं । दो साल के बाद 5 प्रतिशत अत्याचार भी हरिजनों पर नहीं होंगे । इन लोगों ने बहुत सारे काम हरिजनों और ग़रीब लोगों के विरूद्ध किये है लेकिन हमारी सरकार उनकी भलाई के लिए बहुत से काम कर रही है विशेष रूप से गांवों में । गांवो में अपराध उनके खिलाफ़ होते थे या शहरों में उन के खिलाफ़ होते थे उन को दूर करने के लिए हम सतर्क हैं । अभी राजस्थान के श्री नाथू राम मिर्धा बोल रहे थे कि चारों तरफ़ कानून की व्यवस्था ठीक नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि इस के लिए जिम्मेदार कौन है । अन्तिम पुलिस आयोग 1902 में बैठाया गया था और उस के बाद अभी तक पुलिस आयोग नहीं बैठाया गया था। क्यों नहीं बैठलाया गया था ? आज आप यह देखें कि पुलिस स्टेशनों पर

पूरी पुलिस नहीं हैं, उन को कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं । न उन को कोई गाड़ी दी गई हैं और न उन के पास दूसरे कोई साधन हैं जिन से अपराधों का पता लग सके । इसके लिए भूतपूर्व सरकार जिम्मेदार है । हमने इसीलिए पुलिस आयोग की स्थापना की है जिससे अपराधों को हम रोक सकें और यह देख सकें कि एक पुलिस स्टेशन पर कितने सिपाहियों की जरूरत है, कितने और साधनों की जरूरत है । ये जितने अपराध आज दिखायी दे रहे हैं इसके लिए भूतपूर्व सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं । अब धीरे-धीरे अपराधों की संख्या में कमी आ रही है । अब पुलिस स्टेशनों पर रिपोर्ट दर्ज हो रही है, पहले यह नहीं होता था । इसकी वजह से भी कानून और व्यवस्था में बाधा पड़ती थी । मैं अपनी सरकार से यह अनुरोध जरूर करूंगा कि वह थोड़ा और सख्ती से काम ले क्योंकि कांग्रेस के बन्धु देश में अव्यवस्था की स्थिति पैदा करना चाहते हैं अगर उन्हें कंट्रोल करना है तो सरकार को थोड़ा और सख्ती से काम लेना पड़ेगा ।

15.00 hrs.

सरकार ने अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा सुधारने के लिए आयोगों की स्थापना की है । इस कदम से इन लोगों की दशा में सुधार होगा । सरकार चुनाव प्रणाली में सुधार करने के लिए भी कदम उठा रही है । आज तक चुनाव प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया । अनुरोध करता हूं कि इसमें तुरन्त सुधार किया जाना चाहिए । जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह 18 साल के व्यक्तियों को मतदान का अधिकार देगी । मैं चाहता हूं कि इस घोषणा को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए । जब 18 साल की एक युवती अपना पति चुन सकती है, 16 वर्ष का अफ़सर राष्ट्र का काम संभाल सकता है तो 18 वर्ष का व्यक्ति लोकतंत्र में मतदान क्यों नहीं कर सकता हैं । इसलिए मेरी मांग है कि 18 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार तुरन्त दिया जाए ।

स्टीफन साहब और नाथूराम जी कह रहे थे कि आर्थिक दृष्टि से हमने कुछ नहीं किया । कल का बजट आपके सामने हैं । इससे पता लग गया होगा कि हम गांवो के लिये क्या करने जा रहे हैं । हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पूंजीपतियों के लिये कर रहे है । मैं कहता हूं कि इंदिरा जी के जमाने में जितनी विदेशी पूंजी इस देश में आयी, उतनी अब नहीं आ रही हैं । उस जमाने में कुछ पूंजीपतियों को बहुत महत्व मिलता था लेकिन आज ऐसा नहीं है । हम गांधी जी की नीति पर, गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं इसलिए हमें भ्रष्ट अफसरों, दिवालिया राजनीतिज्ञों और बड़े-बड़े पूंजीपतियों का प्रहार सहना पड़ रहा है । फिर भी आप कहते हैं कि हम पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं । हमने अपने बजट का 40 प्रतिशत सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए रखा है । गांवों को और अधिक बिजली दे रहे है, गावों में सड़कें बना रहे हैं छोटे-छोटे स्कूल और छोटे-छोटे उद्योग धंधे खोल रहे हैं । क्या यह गांवों का या देश का विकास नहीं हैं ? हम देश में विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था लाना चाहते हैं । हमने बड़े नोटों का बिमुद्रीकरण किया । क्या यह बहुत बड़ा काम नहीं है ? एक-एक हजार के नोट बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने जमा किये हुए थे, वे सब बेकार हो गये हैं । क्या यह बड़ काम नहीं है ?

इसके साथ-साथ हमने मजदूरों को बोनस दिया । आपातकाल में जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया था उन्हें वापस लिया । हमने ट्रेड यूनियन के अधिकार बहाल किये । मजदूरों की जो भी समस्याएं हैं उनको हम दूर कर रहे है । क्या ये सब थोड़े काम हैं ?

[श्री नाथू सिंह]

मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान में अन्त्योदय चलाया। जो पहले कहते थे कि हम गरीबी दूर करेंगे वे गरीबी तो दूर कर नहीं पाए लेकिन खुद दूर हो गए। लेकिन हम जैसे ही सत्ता में आए हमने गरीबी दूर करने का काम शुरू कर दिया है। अन्त्योदय योजना है। श्री नाथू राम मिर्धा ने कह दिया है कि कोई विकल्प नहीं है। इस योजना में हर गांव में पांच परिवारों को लिया जाएगा। सबसे जो गरीब हैं उनको चुना जाएगा। उनके लिए मकान बना रहे हैं उनको जमीन अगर उनके पास नहीं है तो जमीन दे रहे हैं छोटी छोटी डेरी की उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं मुफ्त में उनके बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था कर रहे हैं। एक साल में पांच परिवारों की गरीबी इस तरह से दूर होगी और पांच साल में एक गांव में पच्चीस परिवारों की दूर हो जाएगी। इतने तो एक गांव में गरीब परिवार भी नहीं होंगे।

पिछली सरकार ने राजस्थान की ओर ध्यान नहीं दिया। राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। वहां जब श्री मोहन लाल सुखाड़िया मुख्य मंत्री थे तब श्रीमती इंदिरा गांधी उनसे खुश नहीं थीं। इस वास्ते उन्होंने उस प्रदेश को आज तक पिछड़ा हुआ रखा है और वहां पर विकास कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया। जयपुर उसकी राजधानी है। उसके अन्दर तक आज तक कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगाई गई। अहमदाबाद में बड़ी बड़ी कपड़ा मिलें हैं। दिल्ली से बड़ी लाइन अहमदाबाद को जयपुर होते हुए ले जानी चाहिए थी लेकिन नहीं ले जाई गई। मैं आशा करता हूं कि जयपुर में बड़ी इंडस्ट्री भी लगाई जाएगी और दिल्ली से अहमदाबाद के लिए जयपुर होते हुए एक बड़ी लाइन देने की व्यवस्था भी की जाएगी।

चूंकि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य है इस वास्ते उसको पिछड़ा राज्य घोषित करके वहां पर छोटे छोटे उद्योग धंधे चालू किए जायेंगे ऐसा भी मैं विश्वास करता हूं।

सरकार ने चीनी और खण्डसारी में जो गड़बड़ी हुई थी उसको ठीक कर दिया है। लेकिन यह कदम कुछ देर में उठाया गया है। मैं चाहता हूं कि किसानों की समस्याओं के प्रति जागरूक रहा जाए और समय पर जो भी कदम उठाना हो उठाया जाए।

फसल बीमा की आज तक व्यवस्था नहीं की गई है। ओला वृष्टि से फसलें बरबाद हो जाती हैं और किसान तबाह हो जाता है। इस साल बेमौसम ओले पड़े हैं। जिन स्थानों पर ओले पड़े हैं सरकार को चाहिए कि छोटे छोटे राहत कार्य वहां चालू करे उन लोगों को जो ओला वृष्टि से प्रभावित हुए हैं सहायता दे। किसानों की फसलों का बीमा हो सके इस प्रकार की व्यवस्था भी सरकार करे ताकि किसान को नुकसान से बचाया जा सके।

शिक्षा में हमने जो परिवर्तन किया है। हमने तय किया है कि निरक्षरता को पांच साल में दूर कर दिया जाए गा। पहले वाली सरकार जो उसके पिट्ठू हुआ करते थे उनको उपकुलपति बना दिया करती थी। हम लोग इसमें परिवर्तन कर रहे हैं और अच्छे शिक्षा शास्त्रियों को विश्वविद्यालयों के उपकुलपति बना कर भेज रहे हैं ताकि शिक्षा जगत में कोई अव्यवस्था का वातावरण न रहे।

बेरोजगारी भत्ते की जिसकी हमने घोषणा की थी उसको हम अभी तक शुरू नहीं कर सके हैं। मेरा निवेदन है कि लो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए तुरन्त रोजगार उपलब्ध कराया जाए और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए चाहे प्रारम्भ में उसकी राशि कम ही क्यों न हो।

अब मैं विदेश नीति के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव

में तटस्थता की नीति पर आज यही सरकार है जो चल रही है। पहली सरकार की विदेश नीति रूस की तरफ झुकी हुई थी। 1956 में जब हंगरी पर रूस ने हमला किया वहां टैंक भेजे तो कांग्रेस सरकार चुप रही कुछ नहीं बोली, वहां पर लोगों की स्वतन्त्रता को जब कुचला जा रहा था तब उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। 1968 में चेकोस्लोवाकिया की जनता ने स्वतन्त्रता की मांग की थी। तब रूस के टैंक वहां गए और लोगों की स्वतन्त्रता की आवाज को उन्होंने कुचल कर रख दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी चुप रहीं, उनकी सरकार चुप रही। वही आज इस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि यह सरकार की नीति अमरीका के अनुकूल है। लेकिन आप देखें कि वास्तविक स्थिति क्या है। सबसे पहला कदम हमने कौन सा उठाया है। सर्वप्रथम हम रूस गए और बाद में अमरीका के राष्ट्रपति कार्टर यहां पर आए। पहले हम रूस की यात्रा पर गए और बाद में कार्टर यहां आए। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बतायें कि हमारी विदेश नीति में क्या खोट है? वास्तव में यह सही विदेश नीति है। हमारे पड़ौसी देशों के साथ सम्बन्ध बहुत अच्छे हो रहे हैं।

चीन के साथ सम्बन्ध अच्छे तो हो रहे हैं लेकिन किस तरह से सम्बन्ध आगे और ज्यादा सुधर सकेंगे यह मुझे मालुम नहीं। बीस अक्तूबर, 1962 को जब कांग्रेस सरकार थी तब इसी सदन में सब लोगों ने खड़े होकर कसम खाई थी कि चीन जब तक हमारी भूमि जो उसने छीनी हैं वापिस नहीं कर देता है या उस जमीन को हम वापिस नहीं ले लेते हैं तब तक हम दम नहीं लेंगे। पिछली कांग्रेस सरकार ने तब से लेकर 1977 तक उस जमीन में से एक इंच जमीन भी वापिस नहीं ली। यह आपकी कूटनीति थी और विदेश नीति थी। आज भी चीन उस जमीन को दबाए बैठा है। लेकिन मुझे विश्वास हैं कि जनता सरकार इस बारे में कूटनीतिक तरीके से काम लेगी और उस जमीन को चीन से बातचीत करके, सम्बन्ध सुधार के, मित्रता कर के वह जमीन को वापस लेगी।

सेन्टर स्टेट रिलेशन्स के बारे में कल कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे। कम्युनिस्ट भाई हमारे कहते हैं कि इस बारे में बातचीत होनी चाहिये। स्टेट्स को ज्यादा अधिकार देने चाहियें। मेरी समझ में नहीं आता कि वह अधिकार लेकर क्या करेंगे। पहले ही उनके पास काफ़ी अधिकार हैं। जो अधिकार स्टेट्स के पास हैं उनको वह किसी को देना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि जिला परिषदों को, पंचायतों को ज्यादा अधिकार दो, जो कि वह नहीं दे रहे हैं। उल्टे स्टेट के लिये और ज्यादा अधिकार मांग रहे हैं। वेस्ट बंगाल के श्री ज्योति बसु द्वारा, कश्मीर के शेख अब्दुल्ला द्वारा और तमिलनाडु में यह मांग की जा रही है। यह वही श्री ज्योति बसु हैं जब 1962 में चीन से लड़ाई हुई थी तो उस समय इन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान ने चीन पर हमला किया है। वह आज ज्यादा अधिकार मांग रहे हैं। शेख अब्दुल्ला जेल से छूटते ही चाउ-एन-लाई से बात करने गये थे, वह ज्यादा अधिकार मांग रहे हैं। तमिलनाडु की सरकार भी कहती है कि स्टेट को ज्यादा अधिकार मिलने चाहियें। मेरा कहना है कि हमारा देश नाजुक दौर से गुजर रहा है, आप रोज उत्तर दक्षिण की लड़ाई करवाते हो, रोज अंग्रेजी और हिन्दी की लड़ाई करवाते हो, जो किसी भी तरह से सही और उचित नहीं हैं। मुझे विश्वास हैं कि इस नाजुक दौर में अगर हमने केन्द्र को कमजोर किया तो इसके परिणाम गलत भोगने पड़ेंगे, हो सकता हैं कि देश की बहुत बड़ा नुकसान हो जाये। इसलिए इस समय स्टेट और सेन्टर रिलेशन्स जो हैं वही ठीक हैं। अगर दोनों में आपस में किसी विषय पर झगड़ा हो तो उसके समझौते की व्यवस्था संविधान में है।

पुनः जनता सरकार ने एक साल में जो काम किये है उसके लिये मैं सरकार को

[श्री ताथू सिंह]

धन्यवाद देता हूं और आशा है कि इसी तरह से आगे भी जनता सरकार काम करेगी और ज्यादा जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये उसे सतर्क होकर काम करना चाहिये ।

श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा (पुरी) : उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं । लेकिन पहले मुझे यह कहना है कि उड़ीसा के 8 एम० पी० ने उड़िया में भाषण देने के लिये कहा था और उसके बारे में एक्स-स्पीकर, श्री रेड्डी साहब से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इस बजट सेशन से इसका इन्तजाम कर देंगे । लेकिन बजट सेशन शुरू हो गया है पर अभी तक इंटरप्रीटेशन का कोई इन्तजाम नहीं हुआ है । उड़िया भाषा का इंटरप्रीटर अभी तक अपौइंट नहीं हुआ, इसका हमें खेद है । हम जानना चाहते हैं कि उड़िया भाषा हाउस में हम बोल सकते है कि नहीं ?

सभाध्यक्ष महोदय : आप बोलिये ।

श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा : इन्टरप्रेटर नियुक्त होने के लिये अखबार में नोटिस भी निकला है । वह इंटरप्रीटर है कि नहीं हमको मालूम नहीं हैं । आप ऐलान करेंगे कि इंटरप्रीटर है कि नहीं ? उड़ीसा की 2 करोड़ जनसंख्या है उनकी भाषा के इंटरप्रीटेशन का इन्तज़ाम क्यों नहीं हो सकता है ? कब तक उड़िया इंटरप्रीटर अपौइंट होगा, यह मैं जानना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी हम कुछ नहीं बोल पायेंगे ।

श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा : हम उड़िया में कहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : बोलिये ।

श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा : **

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can continue to speak in Oriya, but please give a translation afterwards for record.

श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा : It is not possible; I will speak in Hindi.

वह बोलते है कि डैमोक्रेसी नहीं है, हम 2 सवाल उनसे पूछते हैं जो लोक-सभा में भाई वहां पर बैठे हैं और कांग्रेस में इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में थे । जिस समय एमर्जेन्सी जारी हुई उस समय कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियरी नहीं थी । जज को कलैक्टर और एस० पी० गाइड किया करता था । इस तरह की मैं एक दो एक्ज़ैम्पिल देना चाहता हूं ।

मैं भी एमर्जेन्सी के 19 महीने जेल में था । मेरा वारन्ट निकाले बगैर और बगैर किसी नोटिस के मुझे गिरफ्तार कर लिया गया ।

हमको ग्राडिनरी कण्ट्रोल रूम में पुलिस लाइन में एक दिन रखा गया । उसके बाद हमको वारण्ट दिया गया । उस वारण्ट में हमारे बाप का नाम गलत लिख दिया । उनको मालूम था मेरा नाम पी० सी० सामन्तसिंहेरा है और हमारे बाप का नाम मधुसूदन सामन्तसिंहेरा है । मैं एक बार एम० एल० ए० रह चुका हूं, दो बार एम० पी० के लिये कंटैस्ट किया है, जिला परिषद् का चेयरमैन 7 साल रहा हूं, जिला बोर्ड का वाइस चेयरमैन रहा हूं, 5 साल तक स्टेट की-आपरेटिव बैंक और सेंट्रल बैंक का चेयरमैन रहा हूं लेकिन उनको मेरे पिता का सही नाम मालूम नहीं, यह देखने की बात है । उन्होंने मेरे पिता का नाम माधव सामन्तसिंहेरा लिखा । पिता का नाम चेंज करना कितनी खराब बात है ? पिता जब ठीक नहीं है तो लड़का क्या कर सकता है ?

मैंने इस बारे में होम डिपार्टमेंट को लिखा है कि हमारी इज्जत बरबाद किया है, हमारे

**Spoke in Oriya.

पिता का नाम बदल गया है, हमको इसके लिये कंपेंसेशन दे । हमने 50 हजार का क्लेम किया है । हमने कहा है कि हम बूढ़े आदमी हैं, हमने प्रैस्टिज लूज किया हैं इसलिये कंपेंसेशन दिया जाये ।

इसी तरह से पुरी जेल में हमारे एक स्टूडेंट और यूथ लीडर को हाइड्रो-सील के आपरेशन के लिये पुरी अस्पताल में भेजा गया । उनके साथ जो व्यवहार किया गया, वह बात आदमी नहीं सोचता है, जानवर सोचता है । उनको चेन से बांधा गया, और हैंडकफ किया गया । उस डेटेन्यु ने इस बारे में कलेक्टर और एस० पी० को कहा, लेकिन वे बोले कि हम क्या कर सकते हैं । हम लोगों ने कहा कि यह इनडोर पेशेंट है, इसका आपरेशन होगा, वह कहां भाग जायेगा, यहां पर पुलिस के सात आदमी मौजूद हैं । लेकिन फिर भी उसे आपरेशन बैड पर जंजीर से बांध कर और हैंडकफ लगा कर रखा गया । क्या यह मानवीय सभ्यता है या पशुओं की सभ्यता है ? श्रीमती इन्दिरा गांधी के दल के लोगों ने इन बातों का समर्थन किया था । लेकिन आज वे लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में डेमोक्रेसी, गणतन्त्र के बारे में कुछ नहीं कहा गया है ।

मेरा एक नौ साल का लड़का है और एक लड़की है । मैं एक्सरे के लिए हास्पिटल के जेनेरल वार्ड में गया था । पुलिस ने मेरे नौ साल के लड़के को वहां मेरे साथ बातचीत करने देने से इंकार कर दिया, हालांकि आम जनता जेनेरल वार्ड में जाती है ।

जिन लोगों ने ऐसे काम किये, आज वही लोग कहते हैं कि जनता सरकार ने गणतन्त्र के बारे में कुछ नहीं कहा है । वास्तव में श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने गणतन्त्र को खत्म कर दिया था---उसे नाम-मात्र के लिए भी नहीं रहने दिया था । न सरकार में, न पार्लियामेंट और विधान सभाओं में और न जुडिशरी में कोई स्वतन्त्रता या गणतन्त्र रहने दिया गया । इस सदन में या विधान सभाओं में माननीय सदस्य जो भाषण देते थे, उन्हें अखबारों में प्रकाशित नहीं किया जा सकता था ।

ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 की मूवमेंट के समय मुझे इमप्रिजन किया था और मुझे थर्ड क्लास प्रिजनर के रूप में रखा गया था । मैं यह कह सकता हूं कि इस वक्त हमारे साथ जो बिहेवियर किया गया, और जो इंडिपेंडेंस तथा फैसिलिटीज हमें दी गई थीं, श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन-काल में उन में बहुत गिरावट और कमी हो गई थी । उन दिनों ब्रिटिश सरकार से भी ज्यादा नीच काम किये गये थे ।

मेरे दोस्त कहते हैं कि आज गणतंत्र नहीं है । वास्तव में देश में अब गणतंत्र की प्रतिष्ठा हुई है । 1946–47 में हमें जो आजादी मिली थी, श्रीमती इन्दिरा गांधी और कांग्रेस सरकार ने उस आजादी को छीन लिया था । लोगों ने स्ट्रगल कर के अपनी आजादी को फिर प्राप्त किया हैं । इस लिए यह आजादी की दूसरी लड़ाई थी ।

पिछले साल प्रेजिडेंट के एड्रेस में कहा गया था कि जनता सरकार न्यूजपेपर्ज और जुडिशरी को इंडिपेंडेंस देगी, आईन सब पर समान रूप से लागू होगा और आईन में एमेंडमेंट कर के लोगों को नागरिक स्वतंत्रता दी जायेगी । पिछले दिनों हमारे देश में दो आईन रहे---एक आईन श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिए और दूसरा आईन आम जनता के लिए । आम जनता के लिए आई० पी० सी० हैं और कोर्ट किसी भी मामले पर विचार कर सकती है । रामचन्द्र जी के युग में, सत्ययुग और कलियुग में, हर एक युग में आईन, न्याय और नीति सब के लिए समान होती थी । लेकिन पिछले उन्नीस महीने के दौरान यह व्यवस्था की गई कि

[श्री पदमाचरण सामन्तसिंहेरा]

प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, पर आईन लागू नहीं होगा वह चाहे कुछ भी करे, किसी कोर्ट में उस पर विचार नहीं हो सकेगा । अमरीका में वाटरगेट के मामले में एक थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट ने प्रैजिडेंट के मुकदमे पर विचार किया । लेकिन यहां प्राइम मिनिस्टर के बारे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं कर सकते हैं । यह कहा गया कि पार्लियामेंट में उन के आदमियों का एक बोर्ड उन के मामले पर विचार करेगा । उन के लिए यह बात है कि आईन ऐसा हो गया कि जूडिशियरी इंडिपेंडेंट हो गई । सब के लिए समान हो गया । राष्ट्रपति हों, प्रधान मंत्री हो, एम०पी० हों, एम एल०ए० हों सब के लिए एक जैसी व्यवस्था हो गई ।

दूसरी बात जो गणतंत्र की है, मैं कहता हूं इस के पहले तक भारतवर्ष की कौन कंट्रोल करता था ।, जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे, उन की लड़की प्रधान मंत्री हुई तीस साल हो गए, कौन यहां इंडिया का शासन कर रहा था ? यह गणतंत्र था ? कौन रूल कर रहा था इंडिया को ? बीच में बहुत थोड़े दिनों के लिए माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधान मंत्री रहे लेकिन वह बहुत कम समय तक थे । उस में उन्होंने कुछ काम किए थे । लेकिन उस थोड़े से समय के अलावा बाकी के तीस सालों में कांग्रेस पार्टी किस के अन्डर में थी देश पर कौन शासन कर रहा था ? गणतंत्र का यह रूप था कि एक फेमिली ट्रेडीशन के माफिक बाप होगा, फिर लड़की होगी और उस के बाद संजय गांधी हो सकता था । एमर्जेंसी के अन्दर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने रेवोल्यूशन नहीं किया होता तो इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी को ही प्रधान मंत्री बनाने का उनका इरादा था, उन की चिन्ता थी,उन का कार्यक्रम था, उन की योजना थी कि उन के बाद उन का लड़का इंडिया का प्रधान मंत्री बने । लेकिन अब जो गणतंत्र स्थापित हुआ है उस में जनता ने उन को बाध्य कर दिया । जनता ने वह काम कर दिया कि अब वह आ नहीं सकेंगे । गणतंत्र की इस प्रकार प्रतिष्ठा हो गई कि आज ही नहीं फयूचर के लिए भी ऐसा हो गया कि कोई गणतंत्र को खत्म नहीं कर सकता है । हमारे आईन मंत्री ने हाउस में बयान दिया है कि कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे ताकि जो कोई भी सरकार कभी आए वह कोशिश भी करे, चाहे भी तब भी एमर्जेंसी जारी न कर सकेगी क्योंकि संविधान में इस प्रकार के संशोधन कर दिए जाएंगे । हमारे विरोधी पार्टी के लोगों को भी संविधान में इस प्रकार का संशोधन करने में शामिल होना चाहिए और संविधान के अन्दर यह संशोधन करना चाहिए ।

गरीबों के लिए स्लोगन लगाया गया कि गरीबी हटाओ और यह कहा गया कि गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए सब कुछ करेंगे । लेकिन हुआ क्या ? 1947 में बिरला हाउस की प्राफीट 30 करोड़ था । जवाहर लाल नेहरू के रिजीम में और इंदिरा गांधी के रिजीम में 900 करोड़ या 1000 करोड़ हो गया । कौन बढ़ रहा है । गरीब बढ़ रहा है या पूंजीपति बढ़ रहे हैं ? टाटा का क्या था ? 1947 में 20 करोड़ या 18 करोड़ रुपया था, अब वह बढ़ कर 700–800 करोड़ हो गया या 1000–1100 करोड़ हो गया । बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता जाता है । लेकिन कहा क्या जाता है कि गरीबी हटाओ । चीनी चीनी बोलने से पेट में मीठा नहीं जायेगा । गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ स्लोगन देने से गरीबी मिट नहीं जायगी । काम करने से मिटेगी । या केवल बात से नहीं मिटेगी, कलम से नहीं मिटेगी, भाषणों से नहीं मिटेगी, रेडियो से यह काम नहीं होगा । उस के लिए काम करने से गरीबी मिटेगी ।

वह कहते हैं कि पोलिटिकल पार्टीज को कोई स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन यह बात नहीं है । अब तो ऐसी व्यवस्था हो गई कि चुनाव के अन्दर भी जो विरोधी पार्टी के लीडर हैं उन को भी रेडियो पर भाषण देने के लिए, अपना प्रोग्राम करने के लिए इजाजत होगी । उस के लिए उन को इजाजत मिलती रही है और उन के प्रोग्राम होते रहे हैं । इसलिए आज जो जनता सरकार कर रही है वह सब के लिए काम कर रही है ।

अब दामों के बारे में कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ । लेकिन अभी जो बुलेटिन निकला है उस में आप देखें, रेलवे बजट हमारा जो पेश हुआ है उस में एमर्जेंसी के मुकाबिले में हमारी इनकम ज्यादा हो गई है, पैसेंजर ज्यादा हुए हैं, गुडस ट्रैफिक बहुत हो गया है । एमर्जेंसी में जितना हुआ था उससे ज्यादा हो गया है। 1977–78 में एमर्जेंसी लागू कर के भी जितना काम नहीं हुआ था बगैर एमर्जेंसी के उतना काम हो गया ।

तीसरी बात ला-एण्ड-आर्डर की है । हमारे यहां ला-एण्ड-आर्डर सिचुएशन इतनी खराब नहीं है, जितनी विरोधी दलों के लोगों ने जाहिर करने की कोशिश की है । जब कोई देश आजाद होता है, तो आजादी का यही मतलब हैं कि उस की जनता को बोलने की आजादी होनी चाहिये, उस की लेबर को आजादी होनी चाहिये, किसानों को आजादी होनी चाहिये कि वे अपनी तकलीफें सरकार के सामने जाहिर कर सकें, अपने क्लेम सरकार के सामने रख सकें और सरकार के द्वारा उन की तकलीफें दूर हों। एमर्जेंन्सी के दौरान ला-एण्ड-आर्डर के बारे में जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, उन से मालूम होता है कि कैपिटल में उस जमाने में जितनी डकैतियां पड़ीं, जितनी चोरियां हुई, उन के मुकाबले पिछले साल जितनी डकैतियां और चोरियां हुई, वे कम हैं । वास्तविकता तो यह है कि उस जमाने में ऐसी बातों की खबरें अखबारों में आती ही नहीं थीं, क्योंकि अखबारों पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था । आज वह स्थिति नहीं है, आज तो हमारे मिनिस्टर, राष्ट्रपति, या एम० पीज यदि कोई बात कहते हैं, तो सब बातें अखबारों में आती हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है । अभी पिछले दिनों हमारे गृह मंत्री ने इस सदन में फिगर्स देते हुए बतलाया था कि पिछले साल के मुकाबले ऐसी घटनाओं की संख्या बहुत कम हुई है ।

हमारे विरोधी सदस्यों ने कहा कि चीजों के भावों में कोई कमी नहीं हुई है । मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम का काम अभी हाल में चालू हुआ है । हमारे यहां जो प्राइमरी कोआपरेटिव सोसायटीज है, सर्विस-कोआपरेटिव-सोसायटीज हैं–उनके जरियें कन्ट्रोल्ड कमाडिटीज एसेन्शियल कमाडिटीज के बिक्री करने का इन्तजाम किया गया है, जिस की वहज से चीजों के दाम गिरने शुरू हो गये है । मैं आप को एक उदाहरण देता हूं—जीरा पिछले साल बहुत मंहगे दामों पर बिका, लेकिन अब उस का दाम काफी कम हो गया है । मैं इस बात को मानता हूं कि जितना कम होने की हम उम्मीद करते थे, उनता अभी कम नहीं हुआ है, लेकिन उस का दाम कम होना शुरू हो गया है ।

आप जनता पार्टी की इकानामिक पालिसीज की देखिये, मल्टी-नेशनल्ज के बारे में रेजोल्यूशन पास हुआ है, काटेज इण्डस्ट्रीज के बारे में रेजोल्यूशन पास हुआ है, बड़ी इण्डस्ट्रीज के बारे में रेजोल्यूशन पास हुआ है । सरकार की नई पालिसी के अनुसार यदि 300 करोड़ रुपया बड़ी इन्डस्ट्रीज में इन्वेस्ट होगा, तो उससे 20 से 30 हजार आदमियों को काम मिलेगा । लेकिन यदि 300 करोड़ रुपया काटेज

[श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा

इण्डस्ट्रीज पर खर्च होगी तो हमारे देश के 30 लाख आदमियों को काम मिलेगा । इसी लिये सरकार की नीति है कि काटेज और स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाये, ताकि देश के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले ।

कुछ शब्द में फौरन कन्ट्रीज के बारे में कहना चाहता हूं । अभी जनता सरकार को पावर में आये एक साल हुआ है, लकिन इस साल में फौरन-कन्ट्रीज के साथ हमारे जो सम्बन्ध बने हैं, उनको आप सब जानते है । हमारे प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री विदेशों में गये । उन्होंने एटामिक एनर्जी के बारे में उन देशों को हमारी पालिसी जाहिर की, उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की नीति एटामिक एनर्जी के द्वारा लोगों को खतम करने की या देश को खतम करने की नहीं है, हम इसका प्रयोग आदमियों को बचाने के लिये, उनकी वैलफेअर के लिये करना चाहते है । हमारी इस नीति को सभी देशों ने पसन्द किया है । पिछले दिनों अमरीका के प्रेजिडेन्ट यहां आये, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री यहां आये, वियतनाम के प्रधान मंत्री यहां आये, उन से हमारी बातचीत हुई और सभी ने हमारी उस नीति का समर्थन किया ।

श्री पी० के० देव : (कालाहांडी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । उड़िया भाषा के इन्टरप्रेटर की यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है.....

उपाध्यक्ष महोदय : वह हो गई है ।

श्री पी० के० देव : कहां हुई है । सब भाषाओं के लिये इन्तजाम हो गया है, अगर उड़िया के लिये भी इन्तजाम हो जाय तो हम लोगों को भी अपनी मातृ-भाषा में बोलने का अवसर मिलेगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: It has been raised and it is being considered.

श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा : कब होगा ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I can't give you a dead-line. The Secretariat will do its best to provide in as many languages as possible. I understand that that is being done.

श्री पद्माचरण सामन्तसिंहेरा : उड़िया के लिये एडवर्टाइजमेन्ट दिया गया था, इन्टरव्यू भी हुआ था, उस का क्या हुआ ?

*SHRI K. RAMAMURTHY (Dharmapuri): Hon. Mr. Deputy Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to say a few words on the President's Address to the Parliament. At the very outset, I regret to say that the President's address is insipid and uninspiring. You must be knowing, Sir, that the Village Munsif in his Report to the Gram Panchayat enumerates the statistics of production etc., in the year of report and also gives a comparison of past year's performance. I am sorry to say that the President's Address is no different from that—giving the performance of his Government in statistics and comparing it with last year's performance. I would have been happier if at least these figures had been true to the achievement of his Government. While during 1977-78, his Government could not achieve anything concrete to its credit, the President has merely read the statistics supplied to him by his Government. Even these statistics are, I regret to say, false.

You will find in the President's address a reference to the decline in wholesale prices. If that is true, I would like to ask: why his Govern-

*The Original speech was delivered in Tamil.

ment has sanctioned additional Dearness Allowances to its employees only yesterday? Does this not show that the prices of consumer goods have gone up which compelled his Government to sanction additional Dearness Allowance? This alone illustrates beyond doubt that even the President of India is fed with false information. The hon. Members of this House must realise how this Janata Government is misleading the entire nation. To this day 342 days have passed after the assumption of Office by the Janata Party at the Centre. I would like to know what is the achievement of the Government in terms of industrial growth or social upliftment. Even the ruling party Members cannot deny that day in and day out during these 342 days this Government has been harping on the happenings during the Emergency and the fall-out of Emergency excesses. Has the industrial production picked up during the 342 days of Janata regime? During the last session of Parliament, a fresh Industrial Policy statement was made. It was claimed in public that the list of small industries has been expanded. Let me tell you how it has been expanded. The fact of the matter is that the old list has been multiplied by incorporating steel chairs, steel tables, steel stools etc., under the term Steel Furniture contained in the old list. There is otherwise no difference between the old list and the new list. Is this the way to encourage the small industries? Even under the new list, has the Government contributed something to the growth of small industries after the proclamation of the new Industrial Policy? That is also not there. So far as the new industrial policy is concerned, I am sure it cannot achieve anything because it lacks in basic tenets of an industrial policy, it is just clothed in superficial sub-stuff.

Now I will come to the labour policy of the Janata Government. Fortunately for me, the hon. Labour Minister is here and I will request him to be present till I finish my speech. During the last session, it was repeatedly announced that Industrial Relations Bill is coming and coming, as if a tiger is going to pounce. I expected that the President would refer to it in the legislative programme of his Government for the coming year. Unfortunately there is no reference to it in his address. That means the Industrial Relations Bill may not see the light of the day in the near future. It is being bruited that the pent-up feelings of the labour are being let out in the shape of frequent agitations and demonstrations I would like to know whether the feelings of labour would be overflowing during all the 342 days and there will be no gap at all. I am afraid that the Janata Government is taking shelter under this plea for its lack of coherent labour policy. There is no effective labour conciliation machinery to settle these disputes. This has inevitably led to 50 per cent fall in industrial production. I am not saying this form the Opposition Bench this has been mentioned in the Economic Survey of the Government of India circulated to us.

The Janata Government boasts that it has restored freedom to the people of India. Can the people feed themselves with these basic freedoms? Can they quench their thirst or appease their hunger with these basic freeddoms? The basic freedoms have helped in prices of essential commodities soaring sky-high. The Owl is blind by the day and has bright vision by night. MISA has been repealed by the Janata Government, yet all the provisions of MISA are incorporated permanently, in the Criminal Procedure Code. In Madhya Pradesh, mini-Misa is introduced to suppress genuine labour movement. Whatever is useful and beneficial to the Government in running the administration is being utilised in one form or the other by the Janata Government and whatever is not needed, it becomes part of Emergency excesses. The Emergency has come and gone and it is not going to serve any purpose if you go on repeating it It will be good for the country if the Janata

[Shri K. Ramamurthy]

Government realises this as early as possible.

This Government is run by a Party, which is a conglomeration of different political parties and groups. These political parties of varying hues are pulling the country in different directions. So many cooks spoil the broth is the common saying in English. Similarly, these various political groups called the Janata Party are pulling the nation in different directions. Nothing worthwhile has been done so far. The English daily from the Capital, the STATESMAN, which is the staunch supporter of this Government and which also takes pride that it has brought the Janata Party to power has editorially commented in headline that last year was a WASTED YEAR.

If you want to do something, there must be a well-defined basic economic policy, labour policy, industrial policy and social policy having a perspective bearing and not churned out day by day. The Government must decide the direction in which it wants to take the country. Let us see how far the Janata Ministers are resonsible and responsive to needs of 62 crores of people. Immediately after coming to power, on one single day there were 8 Ministers in London, the capital of England as if their coming to power was just to go abroad. This cannot be refuted. It has come in the newspapers. Questions had been asked and answered on the floor of this House. You can imagine how they would have administered the nation in those days. Here also, it had become a habit with Shri Raj Narain to poke his nose in all unwanted things. Sitting in London he raised the language controversy in India. He stated that Tamil is a *Dasi* language. Here in this part of the country *Dasi* may mean slave or servant, but in Tamil *Dasi* means postitute. From that day I have been excepting Shri Raj Narain to visit Madras so that we could honour him suitably for exponding a new theory that Tamil is a *Dasi* language. But he has not yet turned up at Madras.

It is frequently stated here that the people of Tamil Nadu should learn the national language Hindi and the people of northern States should learn at least one language of the Southern States. What arrangements have been made in northern States for teaching one of the Suothern languages? In Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar, Hindi has been made the sole official language; in other words, unilingual policy is being followed in the northern States and the Southern States are advised to adopt trilingualism. Is this the way that the Central Government implements the trilingual policy? Sir, it is not good to make Geetopadesa sitting on a volcano. The devil of separatism will rear its ugly head and the nation will come to suffer, if this policy continues.

When Shri Bala Pajanor of All India Anna D.M.K. was referring to the inexorable attitude of the Prime Minister in not being unwilling to talk to political parties about Centre-State relations, I felt that our Prime Minister is also showing signs of autocracy. It looks that if the third eye of a dictator opens, everything around is burnt. Only an autocrat will say that he shall not talk to other political parties on this subject. At least it does not denote our Prime Minister's democratic inclinations.

The hon. Members who preceded me referred to so many Commissions appointed by the Janata Government. Here the question arises—what for these Commissions have been appointed and for whom they have been appointed. I am confirmed that they have been constituted to give jobs to retired Judges who are favourites of the Janata Government and to disgruntled unemployed politicians who are not being provided jobs in the

Government so far. If that is not done, then many may hoist the flag of protest like Shri S. K. Patil. Asoke Mehta has been made the Chairman of a Commission. Now Minoo Masani, the great socialist, has been made the Chairman of the Minorities Commission. Sir, you tell me—don't laugh at this question—whether Minoo Masani is a socialist or a rank reactionary of the 20th Century.

I agree that the Prime Minister is getting aged. Let him grow old, but let his wisdom also grow. At the same time his thinking should be young. Ootherwise, he will take back the nation to the year of his birth. He should have a perspective of 20 years ahead and then plan for the needs for the nation. I have no hesitation in saying that the President's address is just to detract the attention of the people from the misdeeds and failures of the Janata Government. The President has become the mouthpiece of all incorrect information and figures of the Government. The President does not refer to the burning issues of the day like unemployment, growth of industries, language, Centre-State relation etc. That is because the President has not been permitted to say what he wanted to say, but he was made to read out the speech prepared by his Government. This Address was imposed on him by the Government. It was such a sordid scene the other day that even the President was asked to speak in Hindi He was not permitted and given his right to deliver his Address in Telugu. Here also he had no freedom to do what he can do under the Constitution. Janata Party did not fail to exhibit its political gimmick here also.

Only a few months back the Prime Minister avowed that his Government would eradicate unemployment within 10 years. Now one year of Janata rule is coming to an end. I wonder whether even a blue-print of a programme for removing unemployment has been prepared within this period. The Prime Minister said that Prohibition would be implemented throughout the country within 4 years. Is this possible of achievement? He goes on fixing a time-schedule without a time-bound programme. Has he given thought to the question of giving employment to millions and millions of young men born 25 years ago within a period of ten years? It is not enough to make statements. The Government must have a plan of action to implement what the Prime Minister says.

I conclude my speech by repeating that the President's address is nothing but a cover for the incapacity and failure of the Janata Government in delivering goods to the nation. I regret to say that the President's address is nothing but an expression of pious platitudes based on incorrect information supplied by his Government.

SHRI GEORGE MATHEW (Muvattupuzha): Mr. Deputy-Speaker, I am sorry to say that I cannot agree wholly with the Address of the President. It is about a year since this government has come to power. What has this government done so far? It is true that the climate of Emergency had been cleared. The President has promised that the Government will be removing MISA. Unfortunately Cr. PC is going to be amended and all the provisions which are going to be removed from MISA will be included in it. I am afraid that after two or three years this Government will have in mind the use of MISA in an amended form in the CrPC.

I do not want to go more into details about that and I shall speak mainly on Centre-State relations the educational policy prohibition policy, and also employment policy. As regards Centre-State relations we have been clamouring for a strong centre with contented States. It is really a pity that the States have hardly any power and whatever power they have can be exercised only with the consent of the Centre.

[Shri George Mathew]

[SHRI D. N. TIWARY *in the Chair*]

Take for instance what happened the other day. By an amendment made by the Centre regarding sales-tax, sales tax on some of the goods exportable from Kerala had been abolished. Kerala lost about 23 crores. Initially the Centre promised that Kerala would get the full amount. After some time when we asked for it, they said that it was not possible to ascertain what was the amount lost by the State. Not a pie has been paid to us so far. Now they say they have to check up what has been lost by the State.

At the time of Independence, our State was foremost in literacy and in per capita income and other things. Today it has become the 9th in per capita income and 12th in per capita spending by our government. From the foremost position, we have come down to this position. Do not think that this has happened because we are not hardworking people. Our people are very hardworking people of our State who are working outside the country are remitting about Rs. 450 crores in foreign exchange; they are our kith and kin and yet we hardly get any foreign exchange for setting up industries, etc. We get the money in rupees. Where are industries which could be brought over to Kerala by the foreign exchange but we hardly get any industries. All this money is utilised for benefits elsewhere. This is not the way to treat us. We should get the industries that are due to us. Otherwise it is an explosive situation; this will not go on for ever.

Another aspect is the educational policy. Has this Government got a uniform National educational policy? Surely, it does not have a uniform National educational policy. Each State has got its own educational policy. Is it going to do any good? Take for instance my State, Kerala, which has got the highest literacy percentage in our country. Our schools are cramped and there are sixty to hundred students in each class. We have been asking for more schools and for more teachers. But, through the Planning Commission, the Government has been objecting to opening more schools and appointing more teachers. They say that without the number of students going up, we cannot increase the number of schools and also the number of teachers. Is it a sane policy? Certainly, it is not. If you have about fifty students in a class, only then the teacher can pay greater attention to them and the standard of education can go up. The Central Government has to take full responsibility for this. Kerala as well as other States must be provided with more funds for this purpose. We would like to have a national educational policy and the ratio between the students and the teacher has to be fixed. Otherwise, how can a poor State like Kerala spend more money for education? This is a very important point.

Now I come to Prohibition policy. I am certainly not against prohibition. I would welcome it only if it is a practical policy. I do not think that it is a practical policy. From our own experience and also from the experience of other advanced countries, capitalist as well as socialist, we have seen that prohibition cannot be enforced. I say this from my experience that it can only be implemented voluntarily. Dr. Sushila Nayar was saying that the income that the Government will lose would come back to the Government through some other source. Even if prohibition is going to be enforced strictly, the bootleggers and the smugglers will be bringing in though not very good liquor, the low quality liquor. Sometimes, it will be poisoned liquor also and we read about this in the newspapers We cannot stop the bootleggers and the smugglers from bringing the liquor. We have seen that even in advanced countries like America, they cannot stop it. Of course it is very good to have prohi-

bition; but since we cannot enforce it, we must be very cautious in this.

The next point is that we will lose income. In my State, we were getting about Rs. 10 crores in 1975 through the sale of liquor and in 1976 it increased to Rs. 20 crores and in 1977, it went upto Rs. 40 crores. How are you going to compensate the State Governments? Otherwise, how can we meet our plan and non-plan expenditure?

Another point is that a number of people will become unemployed. There are thousands of people who are today tappers. How are you going to compensate them? Has the Government any precise plan to see that these people are re-employed in some other way so that they get what they were previously getting as today tappers? It does not have any such plan. It is really a pity that so many people will lose their jobs because of a policy which is not going to work at all. So, the Government—if at all they impose this prohibition policy—will have to give them unemployment benefit. But the Government is not going to give them this. That is definite. Already the number of unemployed is going up year by year and you are not going to provide these people with employment.

16.00 hrs.

I am sorry that the Government has said that it is going to solve the unemployment problem in 10 years. Who knows whether you are going to be in power for 10 years? You should tell us what you propose to do within the next four years and what you have done in the past one year. During the last budget session, I said that the unemployment problem should be tackled at a national level and suggested that employment exchanges should be set up at the national level with branches in every State capital. All the educated unemployed should be asked to register themselves with these exchanges and should be provided with jobs on first-come-first-served basis in public sector undertakings, in the order of their merit. Only then the people can feel that they belong to one India. Otherwise, the other States will not give them jobs. In Kerala, there are so many educated unemployed and the number is increasing every year. There are hardly any industries coming up in that State. Our people are forced to go out for jobs. If you calculate it on the percentage of the population, the maximum number of passport applications are from Kerala. They opened one office in Cochin recently and again they have been forced to open another office in Calicut because our people are not getting jobs in India and they have to go out. They are remitting money to the tune of Rs. 450 crores into India. Is this government doing anything to start industries in our State? It is a pity they are doing nothing in this regard.

Coming to the language issue, I wonder why the President was apologetic when he said he could not speak in Hindi. He can speak in either English or Hindi. Don't think I am a language fanatic. I had taken Hindi as my second language in college, although I could have taken Malayalam, my mother tongue. But I took Hindi to learn another language. So, if the Hindi-speaking people also adopt such an approach and learnt another language, it will be very good. The problem is, we feel that you people are forcing something on us. Even people like me, who cannot speak fluently in Hindi but who can understand Hindi, feel we have to resist just for our survival, when we see that you are thrusting Hindi on us. In the Question Hour, we have to speak only in Hindi or English, even though we have interpreters; whereas you people can speak in your own mother

[Shri George Mathew]

tongue always in the House. If you do not insist on Hindi so much, from our side also we will not be so vehement. If you send letters to Tamil-Nadu, Kerala and the southern States in Hindi with or without an English translation, we feel you are going to impose Hindi on us.

There are other points I want to mention about railways, price policy, etc., but I will conclude by saying that the government should have a progressive, forward-looking policy, which is beneficial to all the people of India.

DR. BIJOY MONDAL (Bankura): Mr. Chairman, Sir, I rise to participate in the debate on the Motion of Thanks on the Address by the President for a brief period to express my point of view.

Sir, this Government has been installed in power by the people of India for five years. But this Government has been functioning for the last eleven months only, and I think this is a probationary period and during this probationary period its functioning is quite encouraging The people want that this Government should succeed. People are questioning us as to what will happen if this Government fails. Will those horrible days of Emergency reappear again? Will the dictator rule the country again? They want that this should not be repeated and so they want that this Government should succeed.

I think during this short period the performance of the Government is quite encouraging and the measures taken by this Government are in the right direction. I found that during this short period our Fundamental Rights have been restored, MISA, DIR and other undemocratic laws have been repealed. The powers of the courts have also been restored and the press is now free. Again, during this short time the Government is contemplating to remove distortions which were made by amending the Constitution and it is going to introduce a comprehensive Bill during the course of this Session.

Sir, I found that during the Emergency electoral laws were changed in such a manner that some people were benefited. It was as if a separate law was made for them. I am glad that this Government is taking steps to remove all those distortions which have been made in the electoral laws.

The institutions of Akashvani and Doordarshan are rather going to be autonomous ones. The Government is taking steps in this direction. I found that facilities to use AIR have been granted to other political parties which were never given during the previous regime. This was unthinkable previously and these institutions were used only for partisan ends.

In the economic field too, this Government shows a good sign of doing things in a better manner. I foud that growth rate has been increased and now the gross national production has increased to 5 per cent in the year 1977-78 in comparison to the previous year which was 1.6 per cent (in 1976-77). The food production is 10 million tonnes more than that of the previous year also.

Land under irrigation has been increased this year, to 2.23 million hectares. These things are quite encouraging. Gram Swaraj, which was the dream of the Father of the Nation, was given the go-by by the previous Government, during the last 30 years. The present Government is moving in the right direction and is taking steps to improve the lot of the people in the villages. 70 per cent of our people live in villages. Their conditions have remained wretched during the last 30 years. I am a man from the village. I live in a drought-affected district in West Bengal, where people suffer from famine al-

most every 2 to 3 years. I hope this Government will sanction money for the drought-affected areas. I have found this mentioned in the budget of our Finance Minister yesterday. This Government is moving in the right direction; and I think it will succeed. This Government has inherited a legacy of unemployment and poverty. The previous Government of Mrs. Gandhi had promised to the people that it will banish poverty. And she said this to the people with great fanfare; but it is actually found that poverty has increased to a great extent. The rich became richer and the poor, poorer. This is the performance of the Congress governments during the last 30 years. I really feel that this Government will succeed. The Railway Budget and the General Budget are pointers in this direction. Naturally, people's hopes and aspirations will not be belied by this Government. If this Government fails, there will be dark days ahead for this country and it will be very disastrous.

The trade union is also free now. But this Government should take steps to see that healthy trade unionism grows. Steps should be taken by Government to see that real trade-union and real representatives of labour are consulted; and measures should be taken to see that they at least get recognition. Some trade unions were supporting the dictatorial regime. But I found that there was practically no labour support for them. But the bureaucrats even now are supporting all these unions, and consulting them. Sometimes they are functioning in such a manner that all those trade unions are getting all sorts of facilities from those bureaucrats. Government should at least come forward and take measures to see that all those trade unions which have no labour support, are de-recognized.

This Government has also taken steps which were not taken by the previous governments, during the last 30 years. This Government is going to supply drinking water to areas to which it was never given during the last 30 years. This Government has promised that it will supply drinking water to all those remote villages where there is no such facility.

It has also prepared a scheme by which every village having a population of 1,000 will get at least one community health worker, who would be provided with certain elementary medicines so that he can treat them. He will also take measures to prevent diseases which are communicable. There will also be a lady community health worker to look after the interests of the mother and the child. These are some of the steps taken in the right direction, which is quite in contrast with the performance of the last 30 years when the previous Government did not provide even the minimum treatment facilities to the village people. Though they promised many things, they did not implement them. For example, I was myself associated with many Committees then in my district, where 40 per cent of the people belong to either Scheduled Castes and tribals or other backward classes. Even though many posts are reserved in the services for the Scheduled Castes and Tribes, they are not being implemented. When I asked of the Minister why it is not being done, the answer was "we are trying to do our level best". But it has remained only as a promise, because higher caste people were appointed even in posts reserved for the Scheduled Castes. In the light of that, I would say that the present Government is moving in the right direction.

In the field of foreign policy we are now really non-aligned. In the earlier period we were favouring some countries with the result that some other countries were against us. Now that distortion has been removed and all countries feel that India is really and truly non-aligned.

[Dr. Bijoy Mondal]

So, all the countries are treating India as their friend, because this climate has been created by our External Affairs Ministry.

With these words, I support the Motion of Thanks on the President's Address.

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa): Mr. Chairman, Sir, some of the portions of the President's Address are really very disappointing. Firstly, in the President's Address it is mentioned that the Government want to perpetuate and codify as a permanent law the Preventive Detention Act in the Code of Criminal Procedure, which is highly objectionable and regrettable We strongly object to such legislation being enacted, because it is worse than MISA. In the election manifesto the Janata Party declared that they would revoke the MISA, but this is another kind of MISA, old wine in new bottle. We strongly object to it and share the views of Hon'ble Member, Dr. Sushila Nayar, on this subject.

Secondly, there is lack of direction on the economic issues facing the nation in the President's Address. There is no effective programme for agriculture oriented rural industries and cottage industries throughout the length and breadth of the country. Some new proposals were expected to be made in the President's Address. These are lacking.

From the Economic Review for 1978-79 just released it is found that industrial production has considerably gone down. In 1975-76 it was 20.5 per cent; in 1976-77 it was 10.4 per cent; in 1977-78 it was 5.2. per cent.

Electricity generation was 13.5 per cent in 1975-76, 11.6 per cent in 1976-77 and 2.5 per cent in 1977-78. The trend for 1978-79 will be quite clear from these figures.

Money supply was 11.3 per cent in 1975-76, 20.3 per cent in 1976-77 and 8.7 per cent in 1977-78. Exports at current prices in 1975-76 were 21.4 per cent, in 1976-77 they were 27.2 per cent and in 1977-78 they were 9.3 per cent.

It will be seen that electricity generation is 2.5 per cent, as a result of which most of the industries throughout the length and breadth of India, not only in a particular region, are lying closed. Not more than 50 per cent of their capacity is being utilised. Why? This is due to shortage of power. That is why electricity generation should have been given topmost priority. I should say it should have been given priority on a war footing.

The President has not disclosed how the Government propose to curb inflationary trends and tackle the unemployment problem which is vast. He has said in his Address that he is happy about industrial relations, but there are peaceful strikes in industries, there are agitations of teachers in U.P. and elsewhere, there is violence throughout the country.

How can he be so happy?

You know there have been murders here and elsewhere. There is no mention of this lawlessness in his Address. We expected that he would give us an idea how to curb inflationary trends, but that is not there. There is no indication how to expand industries in the backward areas as also village an cottage industries. He has not mentioned that a Cabinet Minister for Scheduled Castes and Scheduled Tribes would be inducted. There is no such proposal. Everybody feels that the case of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be considered favourably, sympathetically. The quota reserved for them in the services should be fully implemented, but unless there is a Cabinet Minister to look after them, all this will not be possible. So, we expected that our hon. President would make some statement about it in his Address.

About Centre-State relations, there may be a dialogue going on. But the States have no resources. There resources should be much higher. So, the States should have enjoyed more economic powers and more autonomy. But in Jammu and Kashmir Section 370 is there Why? That Article should be abrogated. Jammu and Kashmir is a part of India, that is a province of India. Why should the people of other parts of India not be allowed to go and settle there? Whey should they be debarred from this? This Article, should not be allowed to continue. As a result of this Article, in other provinces there is serious thinking likewise.

There are constant agitations of teachers and industrial workers. These agitations should have been stopped. The State Governments should have looked into it and the Centre also cannot avoid its responsibility.

In a democratic set up, the question of Union territories should also be looked into. Their case is being ignored. In Andaman and Nicobar Islands, some foreigners are coming and settling there. This should be stopped. There is no such mention in the President's Address.

The Commerce Minister is here. I know, he is a capable person. I want to tell him that the public distribution system is a must. There should be a vast programme of enlarging the public distribution system so that goods can reach the consumer at reasonable rates in villages, in all corners of the country. I am sure the Minister will look into it.

I want to say something about the development of industries in the eastern region There has been an agreement with Bangladesh on the distribution of Farakka waters the Government of India has appeased the Government of Bangladesh by giving a lion's share of Farakka waters, keeping with the eastern region only 20,000 cusecs of water and as a result of that, Calcutta and Haldia ports are getting dry. These ports will not survive as a result of which development in eastern region will not be possible. Industries will not grow and there would not be development. So, all these points should have been touched upon in the President's Address. We consider the President's Address as a very valuable document and we have to be guided by this Address. So, unless the industries are developed, unless electricity generation is improved the unemployment problem will not be solved as a result of which there will be revolution in the country. Lakhs and lakhs of people are unemployed. There is no proposal for unemployment allowance in the President's Address. There should be unemploment allowance. In UK and USA, there is social security allowance. Such allowance should have been provided for in the Address. I would request the Government, the hon. Ministers who are sitting here, to look into it and see that such provisions are made in the Budget. Budget estimates have been presented and we shall discuss the matter there.

The problem of unemployment in India is alarming. In West Bengal alone, there are over 20 lakhs of registered unemployed people. There are also other eunemployed people who are not registered. If industries cannot be developed there, if new industries cannot be set up there, there is no possibility of solving the unemployment problem. The electricity generation should be stepped up. Much more money should be provided for this item so that the projects which have been hanging since very long can be implemented. There was a super thermal power project in Farakka. That has been hanging since long and that has not been implemented yet. Adequate provision should be made to see that such projects can be implemented everywhere.

With these words, I conclude.

चौधरी ब्रह्म प्रकाश (वाहय दिल्ली) : चेयरमैन साहब, आज जनता सरकार की एक साल की हुकूमत के बाद मैं खड़ा हुआ

[चौधरी ब्रह्म प्रकाश]

हूं बोलने के लिये। पहले जो प्रैसीडेंशियल ऐड्रेस था उस पर भी मैं बोला था, लेकिन वह रस्मी तौर पर था। यह मेरा 15वां साल पार्लियामेंट में चल रहा है। आम तौर पर मैंने कभी ज्यादा बोलने की जरूरत महसूस नहीं की, सिर्फ प्रैसीडेंशियल ऐड्रेस पर बोला करता था। अभी भी बड़ी रस्म निभा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना होगा। एक फीलिंग है जो मैं कह देना चाहता हूं एक मित्र के नाते। जनता पार्टी और प्रजातन्त्र के मित्र के नाते। जनता पार्टी ही आज के वक्त में ऐसी पार्टी है जिसने और जिसके नेताओं ने प्रजातन्त्र को बचाया, हमें अथौरिटेरियन रूल से मुक्त किया और आज हम आजादी की सांस ले रहे है लेकिन मैं अपनी पार्टी के नेताओं से यह कह देना चाहता हूं कि जनता ने हमें जनता पार्टी समझ कर नहीं बैठाया है, बल्कि इन्दिरा गांधी की कांग्रेस बन गई था उससे नफरत पा कर जनता ने हमारा सहारा लिया। हमारे से मोहब्बत नहीं पैदा हुई। हमको वह मोहब्बत पैदा करनी है। हम अभी तक कहते हैं कि गाड़ी के चार पहिये होते हैं, (फोर व्हील इन दी कोच)। यहां हैं 5 पहिये, और पांचवां व्हील आम तौर पर सुपरफ्लुअस समझा जाता है। मैं तो छठा व्हील हूं बल्कि उसका एक स्पोक हूं जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है और इस वास्ते मैं कितना यूजलैस हूं यह भी मैं जानता हूं। और इसी कारण मुझे परेशानी हुई आज कि मैं यहां बोलूं कि नहीं। मगर मैंने फैसला किया कि मैं बोलूगा जरूर, क्योंकि मैं कभी गैलरी के लिये नही बोलता हूं, न बोला हूं जिन्दगी में। न मैं कांस्टीट्यूएंट्स के लिये बोलता हूं और न कभी बोला हूं। मैं अपनी कोशेंस के लिये बोलता हूं और उसी के प्रति जिम्मेदार हूं। क्योंकि हर पार्टी से ऊपर, हर उसूल से ऊपर आदमी की अपनी कांशेंस है। यह मैं नहीं कहूंगा कि मेरी सही कांशेंस है। हो सकता है कि गलत हो। लेकिन मैं अपने प्रति ईमानदार रहना चाहता हूं और बोलता हूं। इसलिये मैंने बोलने का फैसला किया।

चेयरमैन साहब, आपको मालूम होगा मैं उन लोगों में से हूं और वही कहता हूं जो मुझे कहना होता है। उससे मैं डरता नहीं हूं। मैं इन्दिरा गांधी से मई 1968 में मिला था, उसके बाद आज तक नहीं मिला। मैं वहां से किसी के द्वारा निकाला नहीं गया हूं, बल्कि खुशामद के बावजूद वहां से छोड़कर गया हूं। क्योंकि जब देखा कि तानाशाही इस देश में बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही हैं, तो मैंने सोचा कि एक आदमी जो पटना में बैठा हुआ है, आज क सेंट है, वही क्रांति ला सकता हैं, उसी क्रांति में शामिल होने के लिये मैं चला गया। आज मैं यहां पर अपनी मर्जी से मौजूद नहीं हूं, एक तरह से दोस्तों के मजबूर करने से हूं।

मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं, यह कल के बाद मेरी राय नहीं बनी है। मैं बहुत घुमक्कड़ आदमी हूं। गरीबों की झोंपड़ी से लेकर बहुत बड़े आदमियों के ड्राइंग रूम तक, जिसे टाइकून कहते हैं, घूमता रहा हूं। सारी मिट्टी की खुशबू या बदबू, जो लोग कहते हैं, उससे वाकिफ हूं।

मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की जो हमारी हुकूमत है, उसकी इज्जत लोगों में दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। मैं उसके आंकड़ों में या बहस में नहीं जाता, हालांकि दे सकता हूं, लेकिन हमें सोचना है कि वह इज्जत क्यों कम हुई है।

हमने तानाशाही को खत्म किया, प्रजातन्त्र की बुनियाद मजबूत की, बजट भी हमारा अच्छा है, कई काम काफी शानदार हुए हैं, फिर क्यों हमारी जनता पर उसका असर नहीं है? बल्कि वह असर गिर रहा

है। आप शायद आंकड़े दे दें कि वहां जीते, बिहार में कल जीते, तो वह भी कल की बात थी। आज गदल गया है, यह समझ लेना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह कमी क्यों हुई है ?

एक दफे मैं गांव में जब अपनी पंचायत का सैक्रेटरी था, तो एक बूढ़ा आदमी था, उससे मैं जरा पेंच की बात करने लगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था और मैं उसको बड़ा सीधा आदमी समझता था। वह कहने लगा कि बाबू जी अक्ल की बात मत करो, हुकूमत करना सीखो। हुकूमत सिर्फ अक्ल से नहीं होती है। उस बूढ़े की बात मुझे अभी तक याद हैं, उस समय मैं 17 बरस का था।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी हमारी हुकूमत नहीं कर रही है, किसी तरह से चल रही है। इसका इम्पैक्ट नहीं है। जो टोन और टैनर है, उसका अक्स भी जनता पर दिनों-दिन घट रहा है बावजूद इसके कि आप अच्छा करें। क्यों यह है ? इस वास्ते कि आपके जो मिनिस्टर हैं, मैं समझता हूं कि काफी से ज्यादा मिनिस्टर्स जो इस गवर्नमेंट के हैं, उनको पावर्स ही नहीं हैं। हरेक मिनिस्टर ऐसे नहीं हैं, कुछ को पावर्स दी हैं, वह काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर के पास पावर्स नहीं है। रोज यह बात सुनते हैं कि अब उसको ड्राप किया जायेगा, उसको निकाला जाएगा। एक भी कैबिनेट मिनिस्टर आपने इधर से उधर किया तो जनता पार्टी टूट जायेगी ऐसी अफवाहें बहुत चलती हैं। मैंने कहा कि मैं फिफ्थ व्हील हूं, सुपरफ्लुअस हूं, सिक्सथ कोच का स्पोक हूं, मगर मैं समझता हूं कि इस तरह गाड़ी का चलना मुश्किल है।

मैं प्रधान मन्त्री से कहूंगा कि वह टोन और टैनर को ठीक करें और लोगों को मालूम हो कि हुकूमत हो रही है, ईमानदारी से हो रही है। लोग भावों की परवाह इतनी नहीं करेंगे, लेकिन जो हुकूमत का टोन और टैनर है, जो हमारे कैबिनट मिनिस्टर्स का टोन और टनर है, वह ठीक नहीं हैं, उसको टीक करना होगा। जब एम०पीज० को अण्डर-सैक्रेटरी जवाब देता हैं कि कुछ मिनिस्टर्स के पास मिलने का वक्त नहीं है, तो जनता का और दूसरे लोगों का क्या होगा ?

एक माननीय सदस्य : ठीक बात कही है ।

चौधरी ब्रह्म प्रकाश : मैं यह कह देना चाहता हूं जब मैं आपके साथ था, तो आपसे भी यह कहता रहा । लेकिन उस समय खुशी है कि पं० जवाहर लाल नेहरू थ । लोग गालियाँ भी देते थे लेकिन खुशी हैं कि उसी को दुनिया याद करेगी, और सब को भूल जायेगी । और भी बातें हैं । मसलन, जो चाहे, सो उर्दू के बारे में कह दे । आप को पता नहीं कि आप इस तरह हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को ठेस पहुंचाते हैं । इस बात को छोड़ दीजिए कि एक मजहब के अलावा दूसरे मजहब के लोग उर्दू जानते हैं । एक मामूली बात पर आप कितनी ठेस पहुंचाते है । आज वे लोग सोच रहे हैं कि हम किधर जायें । याद रखना कि अगर आप से इस तरह की भाषा बोलनी जारी रखी, तो वे चले जायेंगे । माइनारिटीज का इस गवर्नमेंट पर भरोसा उठता जा रहा है ।

जहां तक नान-हिन्दी लोगों का सवाल है, हिन्दी का जोश तो बहुत है । हमारे साथी आये हैं और कहते हैं कि तीस साल में कुछ नहीं हुआ । मैं कहना चाहता हूं कि एक बात जरूर हुई कि दूसरी लैंग्वेजिज की पूरी पूरी इज्जत रखी गई । पंडित जवाहर-लाल नेहरू के बाद इसी हाउस से यह चाहा गया कि उस पालिसी को बदला जाये ।

लेकिन श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उसे कायम रखा । श्रीमती इन्दिरा गांधी के

[चौधरी ब्रह्म प्रकाश]

साथ मेरे सौ इख्तिलाफ़ात हों, लेकिन उन के मुताल्लिक मैं यह जरूर कह सकता हूं कि कम से कम वह सकुलर जरूर हैं, कुछ और हों या नहीं । यह हिन्दुस्तान बगैर सकुलरिज्म के नहीं चल सकता है । सकुलरिज्म का मतलब यह है कि हम खाली धर्म और माइनारिटी के झगड़े में न पड़े रहें । माइनारिटीज का ख्याल करना हमारा धर्म है ।

आज अजीब अजीब बातें एक सवाल के जवाब में कही गई । कुरेशी साहब ने सवाल किया था । जब पांच सौ आदमी चुने जाते हैं और उनमें एक भी माइनारिटी के आदमी को नौकरी न मिले, इस पर मुझे शर्म आती हैं ।

नान-हिन्दी बेल्ट आपसे नाराज हैं सिर्फ इस बात पर कि हिन्दी के बारे में जिम्मेदार लोग, कैबिनेट मिनिस्टर, मि० राज नारायण कुछ बातें कहते हैं । राज नारायण साहब ने आपोजीशन की है । लेकिन इस वक्त वह कबिनेट मिनिस्टर है और इस वक्त के चार पांच इम्पार्टेन्ट आदमियों में से हैं । वह जो बात कहेंगे, वह कैबिनेट की बात समझी जायेगी । या तो आप उन्हें दुरुस्त करें, या आप उन से कहें कि मेहरबानी कर के आप पब्लिक में काम करें, आप मिनिस्ट्री नहीं कर सकते । यह बात मैं सफाई के साथ कह देना चाहता हूं । वह मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मैं उन की कद्र करता हूं । लेकिन जितना नुक्सान जनता पार्टी को श्री राज नारायण ने पहुंचाया है, मेरे ख्याल में उतना नुक्सान किसी और आदमी ने नहीं पहुंचाया है ।

फ्लैग का सवाल उठाया गया है । मेरी समझ में नहीं आता कि फ्लैग का सवाल क्यों उठाया जाता हैं । हमने बहुत गलतियां की हैं । मेरी राय में इतने ज्यादा कमीशन बना कर भी गलती की है । खैर, ठीक है, बन गये । मेरी राय में हम ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को गिरफ्तार कर के उन्हें हीरोइन बना कर भी गलती की हैं । अब झन्डे का सवाल उठाया जा रहा है । याद रखिये कि मां बहुत प्यारी होती है, लेकिन लोगों को मां से झंडा ज्यादा प्यारा होता है, चाहे वह कितना ही कमजोर झंडा हो । इस साइकालोजी को भूल न जाइये । इस लिए मेहरबानी कर के इस सवाल को ड्राप कर दीजिए । खुदा के लिए यह झंडे का सवाल न उठाइये । मैं मान सकता हूं कि विरोधी जो कुछ कहते हैं, उस में से हर एक बात गलत है, लेकिन मैं अपनी बात कहने का उनका हक जरूर रखना चाहता हूं । अगर मैं अपने झंडे के लिए जान दे सकता हूं, तो मैं उन्हें भी हक देना चाहता हूं कि वह अपने झंडे के लिए जान दें । उस का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है ।

आज डिफेक्शन्ज के बारे में आप का टोन और टेनर क्या हैं ? आप ने डिफेक्टर्ज को लिया है । जो आये हैं, वे मेरे मित्र हैं । लेकिन नहीं लेना चाहिए था । आप बिल बनाने जा रहे हैं । लेकिन आज आप पावर में हैं । हम कांग्रेस के बारे में भी यही बात कहते थ । मैं उन लोगों में से था, जो जब वे इस तरह का काम करते थे, तो आपोजीशन करता था । लेकिन आप डिफेक्टर्ज को बहुत जगह दे रहे हैं । क्या बगैर पावर के आप किसी स्टेट में नहीं रह सकते हैं ? हम पावर में नहीं रहेंगे, तो क्या बात है ? अगर दूसरे पावर में होंगे, तो क्या हो जायेगा ? इस से भी हम ने अपनी इज्जत को कम किया है ।

प्राइमिज के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा । श्री जय प्रकाश नारायण के जरिये रेवोल्यूशन प्राइसिज और अनएम्पलायमेंट के सवाल पर शुरू हुआ था । मैं अनएम्पलायमेंट के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं— लम्बा सवाल हैं । लेकिन प्राइसेज के बारे में मैं यह कह देना चाहता हूं, ठीक है प्राईसेज

कम हुई हैं कुछ चीजों में, लेकिन जनता से जा कर पूछिए, जो मन्थली पाकेट आता है उस में क्या पड़ता है । मेरी बीबी मुझ से क्या कहती है ? आप मिनिस्टर साहबान घर में जा कर अपनी बीबी से पूछें, आप की बीबी क्या कहती है, जो तनख्वाह ला कर घरों में देते हैं उस का क्या हाल होता है और हम तो खैर, अच्छे खासे खातेपीते लोग हैं लेकिन जो जनता है उस का क्या हाल होता होगा । मैं उस चीज में ज्यादा नहीं जाना चाहता । ठीक है, एक वक्त पर वह चीज आएगी लेकिन जैसे एकदम, शुगर केन का मामला खराबी में गया उस में आप ने अभी तक जो स्टेप उठाने चाहिए थे वह नहीं उठाए, ऐसा मेरा ख्याल है । उस विभाग के मंत्री बैठे हैं, मैं उन से कहूंगा अगले साल शुगर का कहत पड़ेगा अगर प्राइसेज ऐसे ही जायेंगी । आप को बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिए किसानों की मदद में एकदम उसी समय आना चाहिए जब कि उन के दाम एक हद से नीचे गिर रहे हैं ।

तीन चार बातें मैं और कहूंगा । अभी तक गुडविल की कमी नहीं है लेकिन पानी तेजी से बह रहा है । यह सन् 77 नहीं है, सन् 78 की शुरुआत है और दिन ब दिन, महीने व महीने इस में यह चीज हो रही है । एक बात यहां मैं यह कहना चाहता हूं, जैसे पहले मैंने कहा कि आप सबक लीजिए कर्नाटक से । कर्नाटक का जो चुनाव था जिस में अर्स साहब जीते हैं, कहते हैं कांग्रेस जीती है, ठीक है कांग्रेस (आई) जिसे कहते हैं वह जीती है, लेकिन उस में जो कुछ हुआ है उस से आप सबक लीजिए । मैं वहां 48 घंटे रहा हूं, मुझे मालूम है । मेरे मित्र जो मुझसे कहते थे कि हम वहां जीतेंगे उन से मैंने कहा था कि आप नहीं जीतेंगे, आप सेकेंड पार्टी वहां पर होंगे । हां, यह जरूर उम्मीद नहीं थी कि अर्स साहब इतनी मेजारिटी ले जाएंगे । लेकिन इस का कारण क्या है वही एक स्टेट है जहां उन्होंने सब से ज्यादा बैकवर्ड क्लासेज, छोटे लोग और माइनारिटीज के लिए काम किया गया है । यहां माइनारिटीज और बैकवर्ड क्लासेज का नाम लिया जाता है, मैं कहूंगा कि कल सवाल उठेंगे, कि आप ने फलां बैकवर्ड क्लास को कितनी सर्विस दी है । आज बाहर उठते हैं, कल यहां उठेंगे, इसी सदन के अन्दर उठेंगे । ये लोग उस परम्परा में नहीं रहने वाले हैं । इस वक्त बैकवर्ड क्लासेज गरीब, माइनारिटीज, आदिवासी, हरिजन ये सब रो रहे हैं, मर रहे हैं । वे तीस साल इंतजार नहीं करेंगे, दस साल इंतजार नहीं करेंगे । वे मुश्किल से चार साल इंतजार करेंगे और चार साल के बाद उखाड़ कर फेंक देंगे अगर आप वह पालिसी अख्तयार नहीं करेंगे जो अर्स साहब ने अख्तयार की । मैं यह आपको एक सलाह देना चाहता हूं । यह बैकवर्ड क्लासेज, माइनारिटीज और गरीब लोगों का समय है । ताकत रखेंगे तो वे अपने हाथ में रखेंगे, नहीं तो क्रान्ति होगी और बड़ी क्रान्ति होगी । आप यह न समझें कि मैं खुद बैकवर्ड क्लासेज का हूं इसलिये उनकी वकालत कर रहा हूं लेकिन मैं आप को बता दूं । काका कालेलकर की जो उन के बारे में रिपोर्ट है, उस में मुझ से पूछा गया था, जब मैं यहां का चीफ मिनिस्टर था, कि क्या क्राइटीरियन होना चाहिए तो उस वक्त मैंने अपने दोस्तों की मर्जी के खिलाफ यह क्राइटीरिया दिया था, वह रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, मैंने कहा था कि जो गरीब हैं, कमजोर हैं, नीचे हैं, वही बैकवर्ड हैं और मैं ने अपने राज में तमाम गरीब तबके जो मिल सकते थे किसी न किसी नाम से उन को सहूलियत दी थी, इस में कोई शक नहीं है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे कांशंस की बात है । हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं । यह न समझें कि यहां चुनाव हो गया और खत्म हो गया । ये अगले चार-पांच या नौ साल बहुत ही खतरनाक है । एक एक कदम हमें ठोक ठोक कर चलना है ।

[श्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश]

अब इस देश में कोई एक नेता नहीं है । और एक बात और मैं यहां कहूंगा, मेहरबानी कर के खुदा के वास्ते, जवाहर लाल जी को अब आराम से चैन करने दें, उन को कुछ कहना छोड़ दें । जवाहर लाल जी ने इस देश की बहुत खिदमत की है । उन्होंने इस देश को बहुत ऊंचा उठाया है । इस देश की जो आज दसवीं हैसियत हैं दुनिया मे वह उन्हीं को वजह से हैं । आज जो हम सेक्युलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं और हम डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं वह उन्हीं की वजह से कर सकते हैं । यह भी मैं बतला दूं, मैं बहुत करीब था उन के । उस वक्त के करीब लोगों में था । जी उस वक्त के लोग हैं वे जानते हैं । कई कई चीजों में मेरे उन से झगड़े भी हुए हैं, लेकिन हां, जिस बात के लिए हम लोग जाते थे वह उन से मनवा लेते थे, अगर पब्लिक प्वाइंट आफ व्यू को लेकर जाते थे । जवाहर लाल जी के लिये यह कहना कि वह इन्दिरा जी को बना कर गये हैं—यह गलत बात है । उनके एक बहुत करीबी दोस्त ने उन से कहा था—मैं उन का नाम नहीं बतलाऊंगा, अगर आप प्राइवेटली पूछेंगे तो बतला दूंगा—उन्होंने कहा था कि आप इन्दिरा जी को काम में क्यों नहीं लगाते हैं, ये खाली हैं, आखिर आप के बाद कौन आयेगा ? वह कहने लगे—"आप नहीं जानते हैं, जिस को अपने ऊपर काबू नहीं है, वह इतने बड़े देश को कैसे काबू कर सकेगी ।" ये शब्द जवाहर लाल जी के थे, जो कभी बाद में लिखे जायेंगे, ऐसी बात नहीं है कि लिखे नहीं जायेंगे । जवाहर लाल इस देश का बेटा था और यह उस का कसूर था कि इन्दिरा गांधी उस की बेटी थी । मैं आप को यह भी कह देना चाहता हूं—महात्मा गांधी और जवाहर लाल की हैसियत इस देश में वही होगी, 100 साल बाद न सही, 500 साल बाद वही होगी, जो हैसियत आज महात्मा बुद्ध को, ईसा को, प्राफेट मुहम्मद साहब को, भगवान महावीर को हासिल है । आप इस बात को समझ लें कि आज भी हर गरीब के दिल में, हर औरत और मर्द के दिल में, हर बच्चे तथा इंटलैक्चुअल के दिल में जवाहर लाल बैठा हुआ है, वे उस को कभी भूल नहीं सकते ।

आज हम एक क्राइसेज में से गुजर रहे है, कोई लीडर नहीं है, अलग-अलग पार्टियां हैं, अलग-अलग स्टेट के नेता हैं, अलग-अलग फिरकों के नेता हैं, कास्ट्स के नेता हैं, गांव के नेता हैं—यह देश कैसे चलेगा ? उस समय भी हमें यह डर था कि इस देश का डिवीजन हो रहा है, हम इन्दिरा गांधी को इल्जाम दे रहे थे और आज भी देते हैं, उन्होंने इस कन्ट्री को डिवाइड कर दिया । जय प्रकाश जी सब को मिलाना चाहते थे, सबको साथ ले कर चलना चाहते थे, लेकिन आज हालत उस से भी ज्यादा खराब है । सिर्फ मोराजी भाई ही इस टीम में एक ऐसे आदमी हैं—

He is first among the equals not only in the party but among all the parties in this House and outside.

इस वास्ते उन्हें सोचना चाहिये कि हम कैसे इस क्राइसेज को पार करें, किस तरह से जो हमारे अपोजीशन के लोग हैं या जैसे वेस्ट बंगाल है, कर्नाटक है, आन्ध्र प्रदेश हैं या काश्मीर है, इन सब को कैसे साथ लेकर चलें ।

अपने कमीशन्ज की हैसियत आप ने देख ली है, मेहरबानी कर के इन कमीशन्ज को वाइण्ड-अप कीजिये, इस से देश का भला होगा । इन कमीशन्ज की कोई वैल्यू आज नहीं रह गई है, इस वास्ते इन कमीशन्ज के लिये सोचना पड़ेगा कि इन का क्या किया जाय । कोशिश यह करनी चाहिये कि किस तरह से हम यहां के सब एलीमेन्ट्स को जोड़ कर ऐसी शक्ल पैदा करें, एक ऐसा फेस बना कर [...]

को चलायें, जिस से देश आगे बढ़ सके, एक-दो नेताओं से देश आगे नहीं चल सकता है। अगर जबरदस्ती चलाने की कोशिश करेंगे तो एक ऐसा क्राइसेज आयेगा—जो इमर्जेन्सी नहीं होगी, मीसा नहीं होगा, कुछ और होगा—यह बात आप अपने पास लिख कर रख लें।

इन शब्दों के साथ, जाहिर बात है कि एड्रेस में कुछ दिशायें दिखाई गई हैं, हमारे राष्ट्रपति जी ने कुछ बहुत अच्छी बातें कही हैं, उस के बाद जो बजट आया है, उस से भी कुछ तसल्ली हुई हैं, उम्मीद है उस पर अमल होगा, इस के लिये में उन को बधाई भी देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि जो प्वाइन्ट्स मैंने आज उठाये हैं, उन को आप जरूर ध्यान में रखेंगे।

श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। यह खुशी की बात है कि जनता सरकार के आने के बाद जनता पार्टी की घोषणाओं के अनुसार यह पहली सरकार है जिस ने ऐसा कार्यक्रम रखा हैं जो जनता के हित के लिए है और जिसको बिल्कुल क्रांतिकारी कहा जा सकता है। आज से पिछले 30 वर्षों में जो सरकारी निर्णय या कार्यक्रम होते थे, वे बराबर जनता के लिए अहितकर सिद्ध हुए हैं और जो भी बजट राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद लाए जाते रहे थे व एन्टी-पिपिल बजट कहलाते थे, जनता विरोधी बजट कहलाते थे लेकिन इस बार जो बजट लाया गया हैं वह 75 प्रतिशत लोग, जो गांवों में रहते हैं, उन के लिए लाया गया है, जिन ग्रामीण लोगों के द्वारा राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग यानी 51 प्रतिशत देश को प्राप्त होता है लेकिन उस जनता के लिए केवल 15 प्रतिशत ही राष्ट्रीय आय का खर्च किया जाता था। यह पहली सरकार है जिसने 40 प्रतिशत का प्रावधान बजट में उन लोगों के लिए किया हैं और यह एक बहुत बड़ी क्रान्तिकारी कदम है। इसके द्वारा गांवों में 75 प्रतिशत रहने वाले लोगों का सर्वांगीण विकास होगा जोकि अभी तक बड़े उपेक्षित रहे हैं और परिपीड़ित रहे हैं। यह पहला बजट हैं जिस में उन के लिए काम प्रारम्भ होने वाले हैं।

विरोधी पक्ष के कई बन्धुओं ने, माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के कई मिथ्या और राजनीतिक आरोप लगाए हैं कि जनता सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जो जनता के लिए हितकर हो। इन के इस तरह के आरोप ग़लत हैं और जो आंकड़े इन्होंने दिये हैं वे सही नहीं हैं। इन के जो नेता हैं, जो वयोवृद्ध नेता हैं, उन्होंने अपने जमाने में जनता के लिए कोई अच्छे कार्य क्रम नहीं रखे लेकिन आज ये इस तरह की बातें कह रहे हैं। (व्यवधान) .... आज जनता सरकार एक नई परम्परा कायम करने जा रही है और प्रतिपक्ष के लोगों को इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है जैसा कि उन के भाषणों से पता चलता है। अभी जनता सरकार को बने एक वर्ष भी नहीं हुआ हैं और वे इस तरह की बातें कह रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

जो भी बजट आए हैं वे जन-हितकारी नहीं रहे हैं और उन्हें आप चुपचाप मानते रहे हैं और व्यक्तिगत रूप के आधार पर आप यह कहते रहे हैं कि इन्दिरा ही भारत है और भारत ही इन्दिरा है जैसा नेपोलियन कहता था "आई एम दि स्टेट" । उस परम्परा को आप मानते रहे हैं ।

आज जो जनता सरकार बनी है, उस के कारण आप को विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार मिल गया हैं जबकि पिछली आपात-कालीन स्थिति में जनता के सभी अधिकार समाप्त हो गये थे और केवल 12 कर्त्तव्य जोड़ लिये गये थे । आज भी अगर वही स्थिति रहती तो आप बोल न पाते । आज फ्रीडम आफ़ प्रेस मिल गई हैं। आज रेडियो, टेलीवीजन और जितने भी प्रचार के तंत्र हैं, सब में विरोधी दलों की न्यूज, उन के समाचार जनता सरकार के मुकाबले में कहीं ज्यादा आते हैं । विचारों के अभिव्यक्ति को आज प्रधानता दी गई है और वे स्वतन्त्र रूप से आते हैं । यह परम्परा हमारी सरकार ने डाली है । आज न्याय-पालिका स्वछन्द है और उस को स्वतन्त्र रखने का जो फ़ैसला जनता सरकार ने किया है वह श्लाघनीय है । पहले अगर किसी के अधिकार पर कुठाराघाट होता था, तो वह कहीं नहीं जा सकता था मीसा जैसे काले कानून के शिकन्जे में बिना कारण बताए जेल के अन्दर लोगों को बन्द कर दिया जाता था। 185 व्यक्तियों को हमारे जिले के अन्दर इस कानून के तहत बन्द कर दिया गया था और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। इसका कोई उत्तर आप के पास है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : शोर ज्यादा होने के कारण वह जो चर्चा हो रही है, वह सुनाई नहीं पड़ रही है ।

सभापति महोदय : वर्मा जी, आप जरा थोड़ा आगे आ कर बोलिये ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने भाषा नीति के बारे में आरोप लगाये । वे कहते हैं कि हिन्दी भाषा हम लोगों पर लादी जा रही है । मुझे तो पार्लियामेंट में ऐसा लगता है कि हम इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट में बैठे है । यहां इस तरह का वातावरण मालूम होती है कि यहां अपनी कोई राष्ट्रीयता नहीं हैं, अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है । उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी भाषा में गीतांजलि लिख कर नोबल प्राइज प्राप्त किया। इसी तरह से सी० वी० रमन ने रसायन विज्ञान पर अपनी पुस्तक बंगला में लिख कर नोबल प्राइज प्राप्त किया था ।

17.00 hrs.

सभापति महोदय : अपनी पुस्तक क्या उन्होंने बंगला में लिखी थी ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जी हां, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था ।

इसलिए मैं कह रहा था कि अपनी मातृभाषा में जो हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह किसी दूसरी भाषा में नहीं कर सकते । इसलिए यह जरूरी है कि हम सभी अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग करें तभी हम उच्च कोठि की अभिव्यक्ति कर सकते हैं । इसके साथ यह भी जरूरी है कि राष्ट्रीय एकता

के लिए एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हम सब को एक सूत्र में बांध सके। मैं समझता हूं कि भाषा के आधार पर जो प्रान्तों का निर्माण हुआ, यही एक मौलिक रूप से गलती हुई है। मैं यह मानता हूं कि हम अपनी भाषा में अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन इसके साथ मैं यह भी मानता हूं कि हमारी एक लिंक लेंगुएज या सम्पर्क भाषा भी होनी चाहिए। सम्पर्क भाषा वह हो सकती है जिसको सभी लोग आसानी से सीख सकें और उसका प्रयोग कर सकें। मेरे विचार में हिन्दी बड़ी सरल और बोधगम्य भाषा है। इसे आसानी से सीखा और पढ़ा जा सकता है। भाषा के सम्बन्ध में जो लड़ाई यहां होती है, वह व्यर्थ है। मैं अभी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश घूम कर आया हूं। वहां पर 80 प्रतिशत लोग अंग्रेजी नहीं जानते, केवल 20 प्रतिशत लोग ही जानते होंगे। लेकिन यहां हम अंग्रेजी का ही प्रयोग करते है। यह व्हाइट कालर मेन्टेलिटि, मेकाले के जमाने की स्लेवरी चली आ रही हैं। इस देश के लिए एक अच्छी परम्परा नहीं कहा जा सकता है। इस स्थिति में तुरन्त परिवर्तन आना चाहिए। इसके लिए हमें अपने विचारों में परिवर्तन करना होगा और यह सोचना होगा कि राष्ट्रीय एकता अपनी भाषा के आधार पर ही हो सकती है।

एक बात नौकरशाही के बारे में मैं कहना चाहूंगा। चाहे कोई भी सरकार आये, यह नौकरशाही प्रशासनतन्त्र पर हावी रहती है। इसकी यह भावना रहती है कि सरकार तो पांच वर्ष के बाद बदल जाएगी, हम तो यहीं रहेंगे। यह आज भी अपना सम्बन्ध पुरानी सरकार से कायम किए हुए है। इस नौकरशाही के कुछ लोग जिन्होंने पदोन्नति पायी हुई हैं वे अभी पुरानी भावना से मुक्त नहीं हो पाए हैं। इस नौकरशाही को यह सोचना चाहिए कि यह प्रशासनतन्त्र भी भारत का है और हम जो चुन कर आते हैं वे भी भारत के ही प्रतिनिधि हैं। उनमें यह राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। जो योजनाएं हमारे देश में राष्ट्र निर्माण के लिए बनती हैं, वे योजनाएं सही तरीके से पूरी होनी चाहिए और उनका सही तरीके से उपयोग होना चाहिए तभी राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। लेकिन इस नौकरशाही की लायल्टी राजनीतिक दलों में विभाजित रहती है। इसके कुछ लोग अभी भी पिछली सरकार के लोगों से हमदर्दी रखते हैं। उनके अब भी बहुत से काय हो जाते हैं लेकिन जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर कुछ करने को कहते हैं तो वह नहीं होता हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाजित रायल्टी से भी गड़बड़ी होती हैं। इसको ठीक किया जाना चाहिये। यह नौकरशाही अपनी रंगीन टिप्पणियों से पत्रावलियों को अनावश्यक रूप से इधर-उधर करती रहती हैं और लोगों को दौड़ाती रहती है। एक वरिष्ठ अधिकारी से दूसरे वरिष्ट अधिकारी की मेज पर चीजें जाती आती रहती हैं और उसी में समय गुजर जाता है और कोई भी निर्णय समय प नहीं हो पाता है। इसका नतीजा यह होता है कि अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है और राजनीति से प्रेरित आरोप प्रतिपक्ष को लगाने का मौका मिल जाता है और यह कहने का मौका मिल जाता है कि यह सरकार दिशाहीन है, यह सरकार राम भरोसे चल रही है। इसलिए जरूरी हैं कि इस चीज़ के बारे में सोचा जाए और कुछ किया जाए। पिछली सरकार द्वारा रखे गए लोगों से ही सरकारी कार्यालय आज भी भरे पड़े हैं। वे लोग हमारी सरकार के मंत्रियों को मिसलीड करते रहते हैं। इसके कई उदाहरण हमारे सामने है। इस तरह की जो चीजें हैं वे बिखराव पैदा करती हैं और गलत निर्णय हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था आप करें ताकि ब्यूरोक्रेसी जो है वह आप पर हावी न होने पाए, उस पर नियंत्रण

[श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा]

रहे। जो कार्य हो वह तत्परता से हो और जो निर्णय लिए जाएं वे युद्धस्तर पर जिस प्रकार निर्णय लिये जाते है उस तरह से लिए जाएं।

मैं समझता हूं कि यह भी जरूरी है कि आपातकाल में जिन लोगों को प्रोमोशन दे दिए गए थे, जिनकी पदोन्नतियां कर दी गई थी उनको भी देखा जाए। मैं समझता हूं कि अधिकतर उनमें इन्दिरा गांधी के परिवार के लोग है। उन लोगों को अनिवार्य रूप से या तो स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिये या सेवामुक्त कर दिया जाना चाहिये। अगर इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता है तो नान सैंसेटिव पोस्ट्स पर उनको लगाया जाना चाहिये ताकि काम में बाधा पैदा न हो और राष्ट्र का काम अवरुद्ध न हो।

बहुत से विभाग है जो केवल श्रीमती इंदिरा गांधी के आदमियों से ही भरे हुए है जैसे इलैक्ट्रोनिक्स का है, एटामिक एनर्जी कमिशन है, स्पेस का है। इन में एक भी दूसरा नहीं है। इससे काम में बहुत बाधा पैदा होती रहती है। इसके बहुत से समाचार अखबारों में भी आते रहें हैं। इस तरह के जो विभाग हैं उनकी तरफ आपका खास तौर पर ध्यान जाना चाहिये।

तीस बरस की आजादी के बाद भी, पिछली सरकार के कारनामों के बावजूद भी अभी भी हम सिंचाई के मामले में मानसून पर ही निर्भर करते है। आपने सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने की बात कही है जिसका मैं स्वागत करता हूं। मैं आपको एक और कार्यक्रम का सुझाव देना चाहता हूं। जितने भी अनएम्प्लायड इंजीनियर्स हैं उन लोगों को एक निश्चित काम करने के लिए आप दें। आप योजना बनाएं और तीन चार गांव एक या दो इंजीनियरों की दें और योजना के अनुसार वे उस गांव के कार्यों को करें, बैंकों से ऋण दिलाने की व्यवस्था की जाए और सरकार की ओर से एक निश्चित प्रति एकड़ के हिसाब से शुल्क निर्धारित कर दिया जाए तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि चार पांच साल में उन गांवों में पूरे तौर पर सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। जिस तरह से सिंचाई की बात मैंने कही अगर उसी तरह से और भी काम करवाए जाएं तो देश का बहुत कल्याण हो सकता है और हर खेत में पानी पहुंच सकता है, देश का उत्पादन बढ़ सकता है और साथ ही साथ लोगों को काम भी मिल सकता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हर ब्लाक पर छोटे छोटे उद्योग लगा दिए जाएं, एक सरकार की ओर से और एक जनता की ओर से लगा दिया जाए और उन दोनों में आपस में कम्पीटीशन हो और क्वालिटी और प्राइस को सरकार कंट्रोल करे तो इससे भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आपको पता चल सकता है कि कौन सा कामयाबी के साथ चल रहा है और कौन सा है जो गिर रहा है कौन सा ज्यादा सफलता प्राप्त करता है और कौन सा कम। अगर सरकारी उद्योग धंधा गिरता है तो उसमें लगे हुए अधिकारियों को दोषी ठहराया जाना चाहिये। उन में भी लोगों को पढ़े लिखे और बेपढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे लोगों को काम मिल सकता है।

जो कल कारखाने जिस स्थान पर बनें वहां पर स्थानीय लोगों के लिए नीचे की नौकरियां 75 प्रतिशत रिजर्व करदी जानी चाहियें और 25 प्रतिशत टेक्नीकल पोस्ट्स उनके लिए रिजर्व कर दी जानी चाहिए। ऐसा किया जाए तो जो कम पढ़े लिखे, बेपढ़े लिखे लोग और टेक्नीकल लोग वहां हैं उन को काम मिल सकेगा। आजकल होता यह है कि कारखाना खोला जाता है तो सारे देश से लोगों को जातपात भाई भतीजावाद आदि के आधार पर भरती कर लिया जाता है। अगर आस पास के लोगों को काम दिया

जाएगा तो वहां की गरीब जनता को काम मिल सकेगा और काम भी अच्छा होगा ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पावर्टी लाइन, गरीबी की रेखा से नीचे जितने लोग हैं, हर परिवार में से अगर एक को भी काम की गारंटी दे दी जाएगी तो वे उन्नति कर सकते हैं और गरीबी मिट सकती है । इस संदर्भ में मैंने प्रधान मंत्री जी को पत्र भी लिखा है । मैं आशा करता हूं कि इस ओर आप ध्यान देंगे ।

एक और बात कहना चाहता हूं कि छोटा नागपुर में कोयला, लोहा, सोना, चांदी, अबरक आदि खनिज पदार्थों का खजाना भरा पड़ा हुआ है जो सारे देश को फायदा पहुंचाता है और विदेशों में भी यहां से माल जाता है । लेकिन इसके बावजूद भी इस क्षेत्र के 82 प्रतिशत लोग गरीबी और बेकारी के शिकार हैं । छोटा नागपुर को अलग करने की बात चल रही है । अगर सरकार ने वहां के लोगों को वहां के नियोजन में, मंत्रिमंडल में उपेक्षा की, सिंचाई कार्यों में, सड़कों के निर्माण में, विद्युतीकरण में उपेक्षा की गई तो निश्चित रूप से विभाजन की मांग जोर पकड़ेगी । सरकार को सोचना चाहिये आज जो व्यवस्था है विकेन्द्रीकरण की उस दशा में छोटा नागपुर को अलग कर देने में कोई हानि नहीं होगी और इससे उस क्षेत्र की जनता का सर्वांगीण विकास होगा और देश का भी विकास होगा । लेकिन जिस प्रकार से बिहार सरकार की तोड़फोड़ की नीति है और यह आवाज आने लगी तो संथाल परगना का विकास प्राधिकरण बनाया जा रहा है ताकि आवाज उठाने वाले लोगों को वहां बैठा दिया जाय । अगर इस तरह की नीति चली तो ठीक नहीं होगा । जो क्षेत्र खनिज पदार्थों से भरा हुआ है वहां के 80, 82 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहें यह उचित नहीं है, और इस क्षेत्र की अधिक दिनों तक उपेक्षा नहीं होनी चाहिए ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति जी, आप किसी को बुलायें, मैं उससे पहले आपकी व्यवस्था चाहता हूं । सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

MR. CHAIRMAN: There is no quorum. Let the bell be rung

17.14 hrs.

[SHRI N. K. SHEJWALKAR *in the Chair.*]

MR. CHAIRMAN: Now there is quorum.

SHRI R. VENKATARAMAN (Madras South): May I begin?

MR. CHAIRMAN: Yes, you may please begin.

SHRI R. VENKATARAMAN: Mr. Chairman, Sir, I did not intend to speak on the language issue in this debate but, in view of what the previous speaker said, it would look awkward if one who followed the debate after him does not meet some of the points which were raised by the hon. Member. The hon'ble Member used some words which are derogatory to the section which sits on this side of the House. If I heard the translation right he said that there are still people who are Lord Macaulay's slaves.

Sir, abuse is not the privilege of one side. Others can indulge in it and the Opposition can indulge in it in a much greater strength than the Government. Therefore, I do not propose to indulge in recrimination. I do not want to repeat the language used by the other side.

[Shri R. Venkataraman]

Sir, many of us on this side are very keen that the national integrity should be preserved and that the language issue should not be an instrument which threatens such integrity. In fact, right from the days of Pandit Jawahar Lal Nehru it has been repeated by successive Prime Ministers that English will continue to be used in Parliament and in Government until the non-Hindi speaking people agree to its substitution. If some of the Members of the Janata party want to change this, they are going behind the solemn assurance given by successive Prime Ministers and I am afraid, they are sowing the seed of disruption.

Sir, you are aware that it is not possible for all the fourteen languages to be used in Parliament. Only this afternoon one gentleman from Oriya spoke and when he spoke in Oriya none of us could understand anything and people requested him to speak either in English or Hindi. Therefore, the hon'ble Members sitting on the other side—particularly those who run the government have to exercise a little restraint on themselves in the matter of language fanaticism and accommodate the feelings of those whose mother tongue is not Hindi. Sir, it is because of this attitude that a number of amendments are being moved through private Bills to the Constitution so that Panditji's assurances be included as a part of the Constitution itself.

Sir, I will not waste more time on this subject except to say that such thoughtless speeches only irritate even those who want to see that national integrity is preserved and national unity strengthened. I woud like to this occasion to say that the Prime Minister may call a meeting of all the leaders of the parties in Parliament as well as meet the Chief Ministers of the States and try to arrive at a consensus on this language issue. It seems to be necessary at this stage of our political life because there is an apprehension that the new party which has come to power some how wants to force Hindi language on the people of India.

SOME HON. MEMBERS: No no.

SHRI R. VENKATARAMAN: I know it is not. I agree with you it is not but you cannot wipe out the suspicion so long as some of the words that are used in Parliament so long as the attitudes that are taken in Parliament give rise to such a suspicion.

That is why I am making this very humble suggestion that the Prime Minister himself must evolve a national consensus on the language issue and try to see that there is no further bickering about language, no constant irritation develops about language and that we get on together.

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

MR. CHAIRMAN: Let the quorum bell be rung—Now, the quorum is there. The hon. Member may continue.

SHRI R. VENKATARAMAN: Mr. Chairman, Sir, there is one other matter in which I would like the national consensus to be evolved and that is in respect of our external relations. It is not proper for a country to speak with different voices in respect of external relations. It does not enhance the prestige and it does not carry any weight abroad. I am very happy, Sir, that in the President's address, it has been mentioned and the hon. Minister for External Affairs has often repeated that the previous Government's policy of non-alignment is being continued without any change. It is therefore necessary for us to see that we present our point of view in the international forum that we retain the continuity of policy, particularly in respect of non-alignment. Sir, non-alignment was a gift which the great Pandit Jawahar

lal Nehru gave to the world. Before that, the concept in international relations was only one of neutrality of not interfering with anything that happens irrespective of the right and wrong. It was Pandit Nehru who gave a new concept in international relaions wherein countries would not join blocs of either side and judge issues on merits and give support to the right cause. India's prestige ever since 1950s had been increasing in international world mainly because of this policy of non-alignment and discriminating support to the right causes. It is a very happy throught that we are also strengthening our relationship with neighbours. Ceremonial visits between countries do help to bring about better understanding and create better impression in each other's country. But my humble suggestion is that ceremonial visits should be followed up by a certain amount of economic aid and assistance to the developing countries around us. India is no longer a mere developing country it is in the state of intermediate development. It is now in a position to offer technological assistance to many of the developing countries of west Asia and Africa. It is able to give scientific and technological help and it is only by giving that kind of help that we can strengthen our relationship with other countries.

Years ago it had been suggested that India should offer in the Economic and Social Council and in the ECAFE, now ESCAP India will undertake hydroelectric potential survey of Indonesia and offer technological assistance in the matter of power distribution in West Asia and technical assistance in the establishment of many industries like paper, sugar, cement and so on in the neighbouring countries and Malaysia. The international pattern of such assistance is that India bears the cost of the experts who are sent to those countries and the local costs are met by the host country to whom the experts are sent. A larger measure of this kind of aid should be undertaken in the year ahead so that we may not merely strengthen friendly relation but also strengthen economic ties. It is only by strengthening economic ties that we will be able to cement the bond of friendship in a stronger measure. The Reserve Bank of India has bemoaned the continued deficits that are run by the States. Our Finance Minister has also been complaining bitterly about the states running in the red. I have some figures that show that three years ago nine states where in deficit, in the red; today 14 states are in the red. The present overall deficit of all the States is Rs 325 crores. It is fashionable to criticise the states that they are unable to contain their non plan expenditure and that they are running into deficit. But it does require careful examination to see what is the reason for the deficits that the states incur. If we do not go deep into the causes we will never be able to solve the problem.

The more abuse of the States will only bring in return abuse of the Centre from the States. In this connection I would plead for greater devolution of financial authority and financial powers to the States. If you look at the distribution of powers and functions under the Constitution, you will find that all those heads of expenditure which are expanding and which are of social service have been invested in the States—Agriculture, Education, Health, Police, Irrigation, Water Supply, Transport, etc. If you look at the heads of revenue that have been allotted to them, you will see that they are all receding revenues, shrinking sources of revenue—land revenue, which is going down, and then agricultural income tax which with the introduction of agricultural land ceilings is at least evaded excise duties which are sought to be given up. The only thing which is an elastic soruce of revenue to the States is the Sales Tax, and that also is sought to be taken away by the Centre from the States. The Constitution

[Shri R. Venkataraman]

fully realised that there is an imbalance in the distribution of functions and revenues and therefore, they provided that certain taxes should be divisible—such as income tax and excise. Now clever Finance Ministers have really subverted the Constitution....

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति जी मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं सदन में गण-पूर्ति नहीं है ।

MR. CHAIRMAN: Let the quorum bell be rung—Now there is quorum. The hon Member may continue.

SHRI R. VENKATARAMAN: I was saying that the Central Government—I am not saying which Government, there is no point in saying that your Government did it or this Government did it—whoever was in power at that time, really distorted the Constitution by transferring some of the powers which are really vesting in the States to the Centre in a surreptitous manner.

Until 1959, income from companies was included in income-tax and it was divisible with the States. In 1959, by a change in terminology—they called it corporation tax—and appropriated the entire money to the Centre. I was Minister in a State for 10 years and I wanted to cry out. Now I have got a chance to cry out. The idea of surcharge on income-tax is one which is intended as a short-term measure for two or three years. For 20 years they have levied surcharge in income-tax which is really a higher income-tax and deprived the States of their share because if it were levied as larger income-tax without being levied as a surcharge, the total amount will be divisible. But they introduced this concept of surcharge on income-tax and thereby deprived the States of their share. Therefore, in these things the Central Government has really acted contarary to the spirit of the Constitution.

The States were then asked at one stage to surrender some of the items of sales-tax to the Centre, promising they will levy an additional excise duty and divide it among the States. On that basis, the sales-tax on cloth, textiles, sugar and tobacco were surrendered by the States to the Centre and additional excise duty was levied, which was divided among the States. But clever Finance Ministers thereafter increased the basic excise duty all the time appropriated the money to the Centre, giving nothing to the States. They have raised it times without number and in the National Development Council a stage came when they refused to even give thtese three items for central taxation. My submission is, th Centre has deprived the States of the legitimate share of taxes which even under this Constitution they are entitled to and thereby made them impecunious mendicants before the Centre.

Then we came to the planning era. Large sums of money were distributed by the Planning Commission. There is no provision in the Constitution for distribution of this kind of assistance except under article 282, which is a miscellaneous provision intended as miscellaneous distribution of grants. Not having the power, the Centre distributed money through the Planning Commission under article 282. The result was, until the Gadgil formula was accepted, i.e dividing the central pool of assistance among the States on certain basic principles—60 per cent on population, 10 per cent on backwardness, 10 per cent on continuing schemes, etc.—it was entirely within the discretion of the Centre to allot whatever plan funds they thought fit to the States. Is it any surprise to you that the States have become mendicant, have become just importuning beggars, have run into debts and they are all in the red?

SHRI CHITTA BASU (Barasat): As the Department of the Home Ministry in Delhi.

SHRI R. VENKATARAMAN: Often times I have heard it said in this House that the Planning Commission is a super Cabinet.

SHRI CHITTA BASU: Very much.

SHRI R. VENKATARAMAN: I will explain it now. I was also a Member of the Planning Commission. The Planning Commission is only a whipping boy of the Central Government. The central Government acts; it determines what is the assistance it will render In respect of Plan every year. The Planning Commission does not raise resources. It has power to ask for more, but not to decide that so much should be given. Actually whatever money is given by the Central Government is distributed between the State Plans and the Central Plan and the Planning Commission cannot add one pie to it. And whenever various Ministries came and asked for money, the Central Ministries were very clever and they pointed the finger to the Planning Commission saying that the Planning Commission allotted only so much. Could the Planning Commission manufacture money? Has it got the control of the Nasik printing press as the Central Government has? Has the Planning Commission the authority to say how much should be increased for these various heads? It has only the power to distribute what has been given. Unless there is gruel in the pot the ladle cannot deal it out to a large number of people. Therefore, the real position is, right again even in the matter of planning it is the Central Government which has this authority.

Sir, there is one other matter which I want to refer on this occasion. In respect of taxes in which the States are interested, under Article 274 the Central Government before bringing any Bill should obtain the sanction of the President. It need not consult the States. They can change or modify those heads of taxes in which the States are interested and all that the Constitution requires is that they should get the sanction of the President for introducing that Bill. The President as you know, is nothing but the Central Government. The President has to act according to the advice of the Cabinet and therefore, it was the Cabinet which decided that the taxes which affect the States should be changed or modified and then gave itself the authority to the President. Therefore, this state of affairs cannot continue. In fact, if this state of affairs continues I am sorry, there will be a great upheaval in the country. It is all right when only one Party ruled the Centre and the States. For whatever differences we had at that time, we had to go and talk to those people and manage. Today the same Party is not ruling all over the country. The States will raise objection at every stage and then you will create bitterness. As a first measure, I would suggest to the Government that they immediately take up and appoint an Inter-State Council and deal with all matters which under Article 263 they should deal in relation to the States. I do not want to read, but I just want to mention that the Inter-State Council should investigate and discuss subjects in which some or all of the States or the Union and one or more of the States have common interest. Today we are not discussing anything with the States The National Development Council in which I had participated several times, is nothing but gala-making. We meet there for one or two days, we just hear some big shots and each one displays his eloquence. We eat our lunch and go away. We have never been able to make any impact on the inter-State relationships. Therefore, I want to mention that at least as a first step, even if you say that it will take time to consider the question of re-aligning and re-arranging the heads of expenditure as well as heads of revenue, at least as an intrim measure you should take up this question of establishing immediately the inter-State Council.

SHRI CHITTA BASU: Are you in favour of re-structuring of the relations itself?

SHRI R. VENKATARAMAN: I am all in favour. I am in favour of the reconsideration of the whole thing.

To some of those who have not been familiar with the political history of

[Shri R. Venkataraman]

India, it may look as if it is a strange demand. On the other hand, the Motilal Nehru Committee which drafted a Constitution for India in 1925-26—it drafted a Dominion Constitution—said that the powers must be vested in the States—the Provinces at that time—and the residuary power must rest with the Provinces. In 1935 when the Government of India Act was passed, the entire nation, the Congress and the Muslim League opposed it. They rejected it; and that was the reason why Congress did not accept office in 1936 and 1937. The 1935 Act has been *ad item* taken into the present Constitution.

I will now give one more instance. In 1942, when the August resolution was passed—I want people to read it—one of the paragraphs of the resolution said that the Federation should be formed of linguistic units, and also that residuary power should rest with the States. Therefore, this idea that there should be a re-arrangement in the matter of relationship between the Centre and the States, is nothing new, and nothing which is adumbrated by Mr. Jyoti Bosu to-day. It has been with the Congress and with nation right from the beginning. Therefore, I say that the financial relationship is so wrong and bad, that unless we betimes take care to set it right, there will be an explosion. To us, not merely financial relations, but also political relation between the Centre and the States are very important.

There is one more subject of equal importance; and that is the question of inter-State river disputes. These disputes are pending with the Government of India for a very long time. This is governed by Article 262 of the Constitution which says that Parliament may enact a legislation for the purpose of settling inter-State water disputes and exclude the jurisdiction of the Supreme Court thereon. Under Article 131 of the Constitution all disputes between the States can be taken to the Supreme Court. Therefore, a law passed under Article 262 excludes the jurisdiction of the Supreme Court in respect of an inter-State water dispute. In 1956, Parliament passed a law called the "Inter-State Water Disputes Act", and according to Section 4 of that Act, where a request under Section 3—i.e. request for reference of a dispute to a tribunal is received from the State Government in respect of any water dispute and (mark the words) the Central Government is of the opinion that the water dispute cannot be settled by negotiations, it can refer the matter to a tribunal. For years and years there were a number of dispute—I have put a question, I will get an answer some time and they have been pending for a number of years. Government of India have not been able to find time to say that they cannot be settled. Decades have passed. They have not said it. They have said that negotiation will go on. You can make the Supreme Court the competent authority and give it jurisdiction to hear disputes in respect of inter-State waters. Alternatively, we can go back to the 1935 Act. Under the Government of India Act, 1935, whenever a dispute was raised, the Governor-General was obliged—it was obligatory for him—to refer the dispute to a commission. When the Commission reports, the Government of India, that is to say, the Governor-General can decide to accept or not to accept it; but it was obligatory on his part to refer it to the commission. Now under the present dispensation of the Inter-State Water Disputes Act, the Government of India is under no obligation to refer these inter-State water disputes to any tribunal. Therefore, many disputes are still pending. They have never found a solution. Either they must invest the jurisdiction with the Supreme Court, or go to the other alternative of the 1935 Act under which they have to refer the matter to a Commission, vesting with them the right to accept or not to accept its findings.

In this connection, I will mention one episode which occurred bofer in-

dependance. There was a dispute between the then Madras Presidency and the State of Travancore-Conin in respect of the sharing of the Periyar waters. There was an agreement for 999 years for the use of the Periyar waters by the Madras State for irrigation purposes. Later on, the Madras Government wanted to use this water for the purpose of generating electricity also The Travancore-Cochin Government objected to it on the ground that it is an additional use for which some payment has to be made. The matter went in for arbitration. The arbitrator decided that since the original agreement envisaged use of water only for agricultural purposes, if it is being used for some other purpose, some compensation has to be paid. So, that dispute was settled and there was harmonious relationship between those two States. If it had not been settled, there would have been bitter quarrel not only then but for generations to come. Therefore, it is necessary that we must settle the inter-State water disputes as quickly as possible. Either you should give jurisdiction to the Supereme Court or decide it yourself, as was done under the 1935 Act.

DR. B. N. SINGH (Hazaribagh): Mr. Chairman Sir, I rise to support the Motion of Thanks to the President for his address to both Houses of Parliament.

It must be admitted by even the worst critics of the Government that the Janata Party lost no time after being voted to power to restore the charished privileges and rights of the people, which were taken away from them on the pretext of enforcing discipline by the India Government. The people have got back their fundamental rights. The sacred right to life, which has been guranteed in the Constitution, has been restored to them. Parliament has also removed the severe limitations and impediments olaced in the functioning of the judiciary. The press, which is supposed to function as the watchdog of the liberty of the individual and the well-being of the community, had lost its purpose during the Indira regime, as many shackles were placed on its functioning. It was functioning as if it was the echo of the Indira Government, trying to voice to the people all the false claims of the then Government. It goes to the credit of the Janata Party that it lost no time in making the press free, and also in taking the initiative in removing all obstacles in the way of the free functioning of the news agencies. Everyone is rightly proud that democracy, civil rights, freedom of speech, freedom of the press and the functioning of the judiciary have been restored. Dictatorship has been buried and democracy reborn. It must be admitted that all this was achieved by the Janata Government in record time and in fulfilment of the great promise made to the people of India in the Janata Party election manifesto.

So, far so good, but there is one disturbing factor which I would like to bring to the notice of the Government. To my dismay I find that there has been a shift in the original thinking. Originally we were very clear that there should be no MISA, that preventive detention should not be there and that the Forty-second Amendment of the Constitution should be rescinded. The party election manifesto has unequivocally condemned all these Act. I quote from the manifesto :—

> "It is a betrayal of the testament of faith that the founding fathers bequeathed to the people and it subverts the basic structure of the 1950 Constitution... It is the culmination of a conspiracy to devalue democracy."

It is becoming evident that the Government is having a fresh look in the matter, and according to the Law Minister there now seems to be a preference to a selective approach to changes. Thus giving qualified respectability to the unmitigated evils of the Indira Government. There is a proposal to maintain the MISA in its diluted form. In my opinion, preventive detention under any name is an evil in all situations and at all times

[Dr. B. N. Singh].

and must be removed. Under no circumstances would I like that the electorate should have the feeling that this is a case of power changing perspective or of a delayed expression or acceptance of a known situation. Therefore, in consonance with the political charter given to us, MISA and all preventive detention measures should be repeated and the Forty-second Amendment must be rescinded.

If, however, it is now realised that the country cannot do without preventive detention, then it must be admitted to the people that our election manifesto was a mistake, and we must give convincing arguments to the people before we try to bring any such legislation before this House. As it is, emotions are running high on account of the mini MISA introduced in Madhya Pradesh and the maxi MISA in Jammu and Kashmir.

MR. CHAIRMAN: He may continue the next day.

17.59½ hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
TWELFTH REPORT

SHRI DIGVIJOY NARAIN SINGH (Vaishali): I beg to present the Twelfth Report of the Business Advisory Committee.

18.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 2, 1978/Phalguna 11, 1899 (Saka)

GMGIPND—L—3740LS